

दिल्ली में मीटर से हो ऑटो किराया का भुगतान हाईकोर्ट ने सरकार से फैसला जल्द लेने को कहा

संजय बाटला

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि ऑटो रिक्शा में किराया मीटर लगाने के नियम का पालन हो और लोग मीटर के अनुसार ही किराया दें। याचिकाकर्ता आनंद मिश्रा ने अपनी याचिका में परिवहन विभाग को दिल्ली मीटर वाहन नियम-1993 के नियम 74 को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश देने की मांग की थी।

नई दिल्ली। ऑटो रिक्शा में किराया मीटर लगाने के नियम को लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मौखिक रूप से कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि लोग नियम का पालन करें और मीटर के अनुसार ऑटो किराया का भुगतान करें। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेल्ला की पीठ ने दिल्ली सरकार को साथ ही जमीनी स्तर पर मीटर से भुगतान के संबंध में रैडम जांच करने का भी निर्देश दिया।

तीन सप्ताह के अंदर सरकार ले फैसला

उक्त टिप्पणी व निर्देश के साथ अदालत ने याचिकाकर्ता आनंद मिश्रा

द्वारा दायर याचिका का निपटारा कर दिया। अदालत ने याचिका को प्रतिवेदन के तौर पर लेकर तीन सप्ताह के अंदर निर्णय लेने का दिल्ली सरकार को निर्देश दिया। याचिका में परिवहन विभाग को दिल्ली मीटर वाहन नियम-1993 के नियम 74 को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

2018 से किराया मीटर लागू नहीं
यह नियम ऑटो रिक्शा/टैक्सियों में किराया मीटर लगाने का प्रावधान करता है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2018 से किराया मीटर चालू नहीं हैं और प्रतिवादियों ने स्थिति को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।

मीटर से नहीं चलने पर यात्री कर सकते हैं शिकायत

इस पर पीठ ने दिल्ली सरकार की तरफ से पेश अधिवक्ता से पूछा कि आखिर लोग मीटर का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। जवाब में अधिवक्ता ने का कि हर ऑटो रिक्शा में एक मीटर होता है, लेकिन आम नागरिक दाम करके उसी हिसाब से किराया देते हैं। मीटर से भुगतान होना सुनिश्चित करने के लिए हर ऑटो रिक्शा में शिकायत संख्या दी गई है और ऑटो चालक द्वारा इससे इनकार करने पर यात्री शिकायत दर्ज करा सकता है।



इस पर पीठ ने कहा कि इसे लागू किया जाना चाहिए और ऐसा नहीं होने पर सरकार को इसकी रैडम जांच करनी चाहिए। पीठ ने कहा कि आपके पास निरीक्षक हैं और उन्हें जमीनी स्तर पर इसकी जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए।

मजबूरी देख ऑटो किराये पर चलती है मनमानी
राजधानी दिल्ली में ऑटो से सफर करना हो और ऑटो चालक आसानी से मीटर से चलने के लिए तैयार हो

जाए ऐसा बहुत कम ही होता है। अगर, साथ में परिवार और छोटे बच्चे हो तो किराये का दाम और बढ़ जाता है। जब कोई सवारी मीटर से चलने के लिए बोले तो ऑटो चालक यह कहकर कानूनी कार्रवाई से बचने की कोशिश करते हैं कि वह तो घर जा रहे हैं। या अभी वह आराम कर रहे हैं। नहीं तो आम तौर पर ऑटो चालक पहले ज्यादा कीमत बता देते हैं और फिर मोल-भाव करके ज्यादा किराया

टैम्पल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)



रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम-डीएल-0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए-4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉर्पोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली 110042

मध्य प्रदेश में अब सरकारी बसों से सफर होगा आसान पहले चरण में 300 इलेक्ट्रिक बस चलाने की तैयारी कर रहा लोक परिवहन

परिवहन विशेष न्यूज

भोपाल में लोक परिवहन व्यवस्था को फिर से शुरू करने के लिए 300 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना है। इसमें तीन श्रेणी की बसें शामिल होंगी। भारत सरकार से 30% सब्सिडी मिलेगी, और राज्य सरकार भी किराया कम रखने के लिए समर्थन देगी। मुख्यमंत्री इस पहल में रुचि ले रहे हैं।

भोपाल : प्रदेश में लोक परिवहन व्यवस्था फिर से शुरू करने के लिए पहले चरण में 300 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी है। इसमें तीन श्रेणी की बसें होंगी। 18 सीट वाली मिनी बस, 32 सीट वाली मिडि बस और 52 सीट वाली बड़ी बस। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए भारत सरकार से भी 30 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। प्राइवेट बसों की तुलना में किराया कम रहे, इसलिए राज्य सरकार भी बसों का संचालन करने वाली कंपनी को सब्सिडी देगी।

राज्य सड़क परिवहन निगम के पास थी 4 हजार बसें

बता दें कि पूर्व में लोक परिवहन व्यवस्था संचालित करने वाले मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के पास चार हजार बसें थीं, अब उसकी लगभग 10 प्रतिशत बसें पहले



चरण में चलाने की तैयारी है। बसों के संचालन के लिए तकनीकी, वित्तीय व अन्य सुझाव प्राप्त करने के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी। इसके लिए शीर्ष एंजेंसी का चयन किया जाएगा।

बस संचालन को लेकर अहम बातों का फीडबैक

डीपीआर में स्पष्ट हो जाएगा कि बसों के संचालन में क्या दिक्कतें आ सकती हैं और

उन्हें कैसे हल किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग पाइंट कहाँ होंगे। संचालन करने वाली कंपनी की क्या ज़िम्मेदारी हो सकती है। किराया कम रहे इसके लिए राशि कहाँ से मिल सकती है। सरकारी सहायता के अतिरिक्त आय के विज्ञापन या अन्य क्या साधन हो सकते हैं। मानव संसाधन की व्यवस्था किस ढंग से की जाएगी।

मुख्यमंत्री ले रहे दिलचस्पी
बता दें कि मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने

लोक परिवहन व्यवस्था फिर से प्रारंभ करने के लिए कहा है। इसके लिए परिवहन विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग योजना बना रहे हैं। पुलिस ट्रेनिंग एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट (पीटीआरआई) से भी सुझाव मांगा गया है। अभी इस पर सहमति बनी है कि सरकार पीपीपी माडल की जगह खुद ही परिवहन व्यवस्था का संचालन करेगी। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में होने वाली बैठक में होगा।

रोडवेज की 20 बसों में लगा जीपीएस, इंस्टॉलेशन होना बाकी, लोकेशन पर रहेगी अफसरों की नजर

मंडनपुर डिपो में 20 बसें हैं। इनसे रोजाना करीब ढाई हजार मुसाफिर सफर करते हैं। अभी तक रूटों पर संचालन के दौरान बसों की निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं है। स्टेशन से निकलने के बाद चालकों का जब और जहां मन होता है बस रोक देते हैं।

परिवहन निगम ने मंडनपुर डिपो की 20 बसों में जीपीएस ट्रेकिंग डिवाइस लगवा दी है। अब इनका इंस्टॉलेशन होना बाकी है। एक सप्ताह में यह काम भी परिवहन निगम पूरा कर लेगा। इसके बाद रूटों पर जाने के बाद भी बसें अफसरों की नजर में होंगी। इससे चालकों की मनमानी पर अंकुश लगेगा। यात्रियों को भी सहूलियत होगी।

मंडनपुर डिपो में 20 बसें हैं। इनसे रोजाना करीब ढाई हजार मुसाफिर सफर करते हैं। अभी तक रूटों पर संचालन के दौरान बसों की निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं है। स्टेशन से निकलने के बाद चालकों का जब और जहां मन होता है बस रोक देते हैं।

कई बार सवारियों के चक्कर में बसों का संचालन भी मनमानी तरीके



से करते हैं। इन्हीं सब पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन निगम ने डिपो की सभी बसों में जीपीएस ट्रेकिंग डिवाइस लगवाई है। इस डिवाइस से अधिकारी अपने दफ्तर में ही बैठकर बसों की लोकेशन आसानी से देख सकेंगे। इस निगरानी के कारण चालक-परिचालक मनमानी नहीं कर पाएंगे। बस के कहीं पर दुर्घटना का शिकार होने पर अधिकारियों व राहत टीम को वहां तक पहुंचने में आसानी होगी।

इसके अलावा बसों में पैनिंग बटन भी लगवाया जाएगा। इससे किसी तरह के संकट में यात्री या चालक-परिचालक इस बटन का प्रयोग कर सकेंगे। इस बटन को दबाते

ही नजदीकी पुलिस थाने में सूचना पहुंच जाएगी। जीपीएस ट्रेकिंग डिवाइस का इंस्टॉलेशन होना बाकी है। अफसरों का कहना है कि एक सप्ताह के अंदर यह काम भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी।

मंडनपुर डिपो की रोडवेज बसों में जीपीएस ट्रेकिंग डिवाइस सिस्टम लगा दिए गए हैं। इन्हें इंस्टॉल करने की प्रक्रिया चल रही है। एक सप्ताह के अंदर यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बसों की संचालन व्यवस्था को और चुस्त-दुरुस्त करने में यह जीपीएस डिवाइस सिस्टम काफी कारगर साबित होगी।

सीबी राम, एआरएम, लीडर रोड डिपो

इलेक्ट्रिक में तीन तो पेट्रोल वाली गाड़ियों में डेढ़ लाख तक की छूट, धनतेरस-दीवाली पर बड़ी कारों की डिमांड

अगर आप भी इस दीवाली और धनतेरस कार या बाइक खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह खबर बिल्कुल आपके लिए ही है। माना जा रहा कि 25 हजार से अधिक कारों की बिक्री इस त्यौहारी मौसम में होने वाली है। 60 हजार से अधिक दो पहिया वाहनों की बिक्री की उम्मीद जताई जा रही है।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में धनतेरस व दीपावली के खास मौके पर दो पहिया व चार पहिया वाहनों की मांग में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। खासकर लोग धनतेरस पर गाड़ी की डिलीवरी चाह रहे हैं। ऐसे भी कम नहीं हैं जो अभी ही कार की सवारी चाह रहे हैं।

ऐसे में कार व दो पहिया वाहन शोरूम में काफी भीड़ भाड़ देखी जा रही है। यह भीड़ नवरात्र के साथ ही शोरूम में पहुंचने लग गई है। विशेषकर एक ही माह में नवरात्र और धनतेरस दोनों पड़ रहा है।

बाजार के जानकारों के अनुसार इस त्यौहारी मौसम में करीब 25 हजार कारों की बिक्री की उम्मीद है। जबकि, 60 हजार से अधिक दो पहिया वाहन बिक जाएंगे। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष वाहनों की मांग में 15 प्रतिशत तक की तेजी देखी जा रही है। विशेषकर 10 लाख रुपये से नीचे

की कारों की मांग (Diwali-Dhanters car discount) में अधिक उछाल है। इस वर्ग में मांग 50 प्रतिशत से अधिक है।

शोरूम संचालकों ने भी कर रखी है पूरी तैयारी

मांग को पूरा करने के लिए इस बार वाहन कंपनियों के साथ ही शोरूम संचालकों ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। अनुमानित मांग के अनुसार स्टॉक मंगाकर रख लिया गया है। इसलिए अधिकतर बुकिंग के मामलों में डिलीवरी में कोई परेशानी नहीं है। हालांकि, एक प्रमुख कार कंपनी के कुछ एक मॉडल की डिलीवरी में 10 से 15 दिन का अतिरिक्त समय लग रहा है। क्योंकि, उन मॉडलों की मांग अधिक है।

वहीं, कार कंपनियों ने दीपावली के मद्देनजर ग्राहकों को लुभाने के लिए नए मॉडल और नए फीचर्स भी लाए हैं, जिसको खरीदारों द्वारा पसंद किया जा रहा है। खरीदारों द्वारा वाहनों की खरीद में जेब को ध्यान में रखने के साथ गुणवत्ता और सुरक्षा व स्मार्ट फीचर्स को भी ध्यान में रखा जा रहा है।

50 हजार रुपये से लेकर डेढ़ लाख रुपये



तक राशि की छूट
आटोमॉटिव पाटर्स मर्चेण्ट एसोसिएशन (अपमा) के पूर्व प्रधान व वाहनों की बिक्री से जुड़े

शंकर लाल अग्रवाल के अनुसार व्यवसायिक व यात्री वाहनों की मांग में पिछले धनतेरस की अपेक्षा अच्छी मांग देखी जा रही है। कंपनियों ने भी अपनी

तरफ से ग्राहकों के लिए कई लुभावने पेशकश की है। जैसे, 50 हजार रुपये से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक राशि की छूट है। इसी तरह, यात्री वाहनों में

कंपनियों ने दाम घटाए हैं। डीजल व पेट्रोल वाहनों में 50 हजार से लेकर डेढ़ लाख तक तो इलेक्ट्रिक वाहनों में तीन लाख रुपये कम किए हैं।

उनके अनुसार, ऐसा इसलिए क्योंकि, पिछले कई महीनों में बिक्री में गिरावट देखी जा रही थी। ऐसे में दशहरा व दीपावली को देखते हुए कंपनियों के साथ डीलरों ने ग्राहकों को लुभाने के लिए सभी प्रयास किए हैं।

इलेक्ट्रिक वाहनों को लगा झटका
डीजल, पेट्रोल व सीएनजी के अपेक्षाकृत इलेक्ट्रिक वाहनों में कमी देखी जा रही है। इसकी वजह पंजीकरण शुल्क में छूट का नहीं होना है। शंकर लाल अग्रवाल के अनुसार, हरियाणा में पंजीकरण शुल्क में 75 प्रतिशत तक की छूट तथा उत्तर प्रदेश में शत प्रतिशत की छूट से लोग पड़ोसी राज्यों से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर जोर दे रहे हैं। दिल्ली में कोई छूट नहीं है।

कारों की मांग में अच्छी बढ़ोतरी देखी जा रही है। यह इसलिए भी कंपनियों ने कई सारे नए मॉडल पेश किए हैं। खासकर सीएनजी के मॉडल में भी अच्छी पेशकश है। जिस तरह से बुकिंग हो रही है और मांग निकल रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में कारों की बिक्री 15 प्रतिशत से भी अधिक रहेगी।

सौरभ अग्रवाल, निदेशक, चेरीस कार्स

दिल्ली में फिर गरजा बुलडोजर, पुलिस और MCD की संयुक्त कार्रवाई में हटाए गए अवैध कब्जे

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली के खजूरी चौक से श्रीराम कॉलोनी रोड तक दोनों तरफ के अतिक्रमण को नगर निगम और पुलिस ने हटाया। इस दौरान रेहड़ी-पटरी वालों ने विरोध किया लेकिन कार्रवाई जारी रही। करीब दो किलोमीटर के हिस्से को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। फुटपाथ पर बनी अस्थायी दुकानों को बुलडोजर से तोड़ा गया और कई रेहड़ियां जक की गईं। अनधिकृत रूप से खड़े वाहनों का चालान भी किया गया।

पूर्वी दिल्ली। नगर निगम ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर शनिवार को खजूरी चौक से श्रीराम कॉलोनी रोड तक दोनों तरफ अतिक्रमण हटाया। इस दौरान रेहड़ी-पटरी लगाने वालों ने विरोध किया। लेकिन किसी की एक न चली। निगम और पुलिस की टीम ने करीब दो किलोमीटर का हिस्सा अतिक्रमण मुक्त कराया गया।

इस दौरान फुटपाथ पर बनी अस्थायी दुकानों बुलडोजर से तोड़ा गया। फल व अन्य सामान की कई रेहड़ियां जक की गईं। अनधिकृत रूप से खड़े वाहनों के कारगर जाम लगा रहा था, ऐसे वाहनों का चालान भी किया गया।

ऑटो और रेहड़ी से रोज लगता है जाम
उत्तर पूर्वी दिल्ली में खजूरी चौक पर सबसे ज्यादा जाम रहता है। ऑटो और रेहड़ी की वजह से यहां पर रोज जाम की स्थिति बन रही थी। इसे लेकर



लगातार शिकायतें निगम के शाहदरा उत्तरी जोन और पुलिस के पास पहुंच रही थीं। इसके चलते दोनों ने मिलकर शनिवार को अभियान चलाया। कार्रवाई शुरू होते ही रेहड़ी लगाने वालों में अफरा-तफरी मच गई। वह अपनी रेहड़ी लेकर जाने लगे।

अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया गया
इस चौक के आसपास कई लोगों ने फुटपाथ पर अस्थायी रूप से दुकानें बना रखी थीं, उसके आगे वह सामान रखते थे। इनकी दुकानों को तोड़ दिया गया गया। यहां से टीम पुरता रोड पर आगे बढ़ी।

वहां श्रीराम कॉलोनी रोड तक सड़क के दोनों ओर अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया गया।

पूर्वी दिल्ली में भी हटाया गया था अतिक्रमण
इससे पहले, पूर्वी दिल्ली में रेहड़ी पटरी हटाने के साथ ही दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर जो अतिक्रमण किया तो उसे हटा दिया गया है। दो किलोमीटर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया गया है। स्पष्ट किया आगे भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

सदर बाजार में भी अतिक्रमण से रहती है

अव्यवस्था

सदर बाजार थाने के इंस्पेक्टर और 11 पुलिस कर्मियों के लाइन हाजिर किया गया था। इसके बाद भी सदर बाजार क्षेत्र को रेहड़ी पटरी वालों के अतिक्रमण से पूरी तरह से राहत नहीं मिली है। विशेषकर पुल मिठाई पर वर्षों से जमे रेहड़ी-पटरी वाले नाशुर बन गए हैं। मामले के जानकारों के अनुसार सदर बाजार में अतिक्रमण की तरह ही पुल मिठाई से अतिक्रमण के चलते खरीदारों के साथ ही दुकानदारों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

'तंदूर को या तो सीएनजी में बदल लें, नहीं तो...'; MCD ने रेस्तरां मालिकों को दी चेतावनी

दिल्ली में वायु प्रदूषण का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इस पर राजनीति भी हो रही है। प्रदूषण को देखते हुए ग्रेप का दूसरा चरण लागू हो गया है। ऐसे में एमसीडी ने नियमों का उल्लंघन करने वाले रेस्तरां संचालकों के खिलाफ एक्शन के मूड में नजर आ रही है। उन्हें तंदूर को CNG में बदलने को कहा गया है।

नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण के मद्देनजर ग्रेप का दूसरा चरण लागू हो गया है। ऐसे में धूल से लेकर कूड़े में आग लगाने की घटनाओं को रोकने के लिए एजेंसियां तमाम दावे कर रही हैं। इस बीच तंदूर में लकड़ी और कागज आदि जलाने पर प्रतिबंध है। इसको देखते हुए एमसीडी ने नियमों का उल्लंघन करके संचालित होने वाले तंदूरों के खिलाफ विशेष अभियान छेड़ दिया है।

ग्रेप का दूसरा चरण लागू होने के बाद एमसीडी 9 रेस्तरां संचालकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की है जबकि 38 तंदूर को नष्ट कर दिया है और 54 रेस्तरां में तंदूरों को सीएनजी में तब्दील करा दिया है। इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए एमसीडी की टीम लगातार रेस्तरां का निरीक्षण कर रही है और

कोशिश कर रही है किसी भी रेस्तरां में लकड़ी का तंदूर में जलाने के लिए उपयोग न किया जाए।

रेस्तरां संचालकों को सीएनजी आधारित तंदूर का उपयोग की सलाह

एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तंदूरों का उपयोग प्रतिबंधित है। इसलिए रेस्तरां संचालकों को सीएनजी आधारित तंदूर का उपयोग की सलाह दी जा रही है। साथ ही नोटिस देने की कार्रवाई भी की जा रही है। जो रेस्तरां संचालक नोटिस के बाद भी सीएनजी में तंदूर को तब्दील नहीं करेंगे उन रेस्तरां को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारी ने आगे बताया कि एमसीडी ने सड़क किनारे पटरी पर खाना बेचने वाले और चार का नान बेज को बनाने के लिए तंदूर का उपयोग करने वालों के तंदूर को तोड़ा जा रहा है। पुनः तंदूर का उपयोग वहां पर शुरू न हो जाए इसके लिए बार-बार निगरानी भी की जा रही है।

एमसीडी अधिकारी ने बताया कि 1000 से अधिक स्थानों रेस्तरां और स्थानों का निरीक्षण किया जा चुका है। एमसीडी की रिपोर्ट के अनुसार तंदूरों के खिलाफ सर्वाधिक कार्रवाई केशवपुरम जोन में की गई है।

शहीद शांति स्वरूप शर्मा की प्रतिमा लिबासपुर गाँव में लगाने की मांग : प्रोफेसर सुमन

सुषमा रानी

फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस के चेयरमैन प्रोफेसर हंसराज सुमन ने दिल्ली के उप राज्यपाल व दिल्ली की मुख्यमंत्री से बाहरी दिल्ली के बदली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लिबासपुर गाँव के चीन - भारत युद्ध में शहीद हुए शहीद शांति स्वरूप शर्मा की प्रतिमा लिबासपुर गाँव में स्थापित करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को एक प्रस्ताव भी भेजा है जिसमें लिबासपुर गाँव में नव निर्मित सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम शहीद शांति स्वरूप शर्मा के नाम पर रखने की मांग की है। प्रोफेसर सुमन का कहना है कि यदि दिल्ली सरकार इनके नाम पर स्कूल का नाम व उनकी प्रतिमा स्थापित करती है तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और भावी पीढ़ी ऐसे महान योद्धा से प्रेरणा लेंगी। उन्होंने उप राज्यपाल व केंद्र सरकार से मांग की है कि शहीद शांति स्वरूप शर्मा के परिवार को उनके बेटे को एक शहीद के रूप में सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

उन्होंने बताया है कि लिबासपुर गाँव निवासी शहीद शांति स्वरूप शर्मा माध्यमिक शिक्षा पूर्ण कर सैनिक के रूप में भर्ती हो गए। ये राजपूत रेजिमेंट में बतौर सैनिक के पद पर रहे। सन 1967 में जब चीन और भारत का युद्ध हुआ तो इनके साथियों ने चीन से लोहा लिया। चीन - भारत युद्ध में शहीद होने वाले भारतीय सैनिकों में से एक थे, बताया जाता है कि उस युद्ध में उन्होंने चीन के बहुत से सैनिकों को मार गिराया था, ये घायल अवस्था में चीन सैनिकों को सबक सिखाते हुए अंत में 12 सितम्बर 1967 को शहीद हो गए। प्रोफेसर सुमन ने बताया है कि गाँव लिबासपुर में उनके परिवार के लोगों ने ओबीसी बैक गली में उनकी प्रतिमा स्थापित की



है। गाँव की युवा पीढ़ी को इस महान योद्धा के विषय में जानकारी नहीं है। प्रोफेसर सुमन ने बताया है कि वे इसी गाँव के मूलनिवासी हैं और जब से उनके विषय में पता चला है वे आसपास के गाँव वालों को शहीद शांति स्वरूप शर्मा के

विषय में बताते हैं कि किस प्रकार लिबासपुर गाँव के इस महान योद्धा ने चीन - भारत युद्ध में लड़ते हुए चीन सैनिकों को मार गिराया था। उनके कई साथी मारे गए अंत में वे चीन सैनिकों की गोली का शिकार हुए, प्राणों की

आहुति दे देश की मातृभूमि के लिए शहीद हो गए।

उन्होंने बताया है कि लिबासपुर गाँव के लोगों का देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, अलीपुर कांड व गाँव में बने पंचपीर उन शहीदों की याद दिलाता है। इसके आसपास धौलाकुंआ, अडाना, समयपुर, बादली आदि गाँवों का इतिहास आजादी के आंदोलन में दर्ज है। इसलिए आवश्यक है कि वर्तमान पीढ़ी इस महान योद्धा के विषय में जाने। फोरम पुनः उप राज्यपाल व मुख्यमंत्री से मांग करता है कि शहीद शांति स्वरूप शर्मा की प्रतिमा लिबासपुर गाँव में स्थापित करने व सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम उनके नाम पर रखा जाए। उन्होंने मुकरबा चौक से लिबासपुर गाँव तक आने वाली मुख्य सड़क का नाम शहीद शांति स्वरूप शर्मा के नाम पर रखे जाने की मांग दोहराई है।

दिल्ली में प्रदूषण का कहर, 13 इलाकों की हवा हुई जहरीली; जानें आनेवाले दिनों में कैसा रहेगा AQI

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। राजधानी के 36 प्रदूषण निगरानी केंद्रों में से 13 जगहों पर एयर इंडेक्स 300 से अधिक पहुंच गया है। इस वजह से इन इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। सीपीसीबी के अनुसार हवा की गति कम होने से रविवार को प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी होने की आशंका है।

नई दिल्ली। राजधानी में लगातार दूसरे दिन क्वालिटी इंडेक्स 300 से कम रहने से हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बरकरार रही। लेकिन देर शाम से एयर इंडेक्स बढ़ना शुरू हो गया। इस वजह से शाम सात बजे दिल्ली के 36 प्रदूषण निगरानी केंद्रों में से 13 जगहों पर एयर इंडेक्स 300 से अधिक पहुंच गया। इस वजह से इन इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार हवा की गति कम होने से रविवार को प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी होने की आशंका है। इस वजह से रविवार से मंगलवार तक दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रह सकती है। सीपीसीबी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का एयर इंडेक्स 255 रहा। एक दिन पहले दिल्ली का एयर इंडेक्स 270 था। इसके मुकाबले एयर इंडेक्स में 15 अंकों का सुधार हुआ लेकिन देर शाम से एयर इंडेक्स बढ़ना शुरू हो गया। इस वजह से आनंद विहार, अलीपुर, अशोक विहार, बवाना, जहांगीरपुरी, मुंडका, नेहरू नगर, पंजाबी बाग, रोहिणी, शादीपुर, सोनिया विहार, विवेक विहार व वजीरपुर में एयर इंडेक्स 300 से अधिक पहुंच गया। वहीं एनसीआर के शहरों में गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा व नोएडा में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही। गुरुग्राम व फरीदाबाद में प्रदूषण से एयर इंडेक्स मध्यम श्रेणी में रहा। इस वजह से इन दोनों इलाकों में प्रदूषण से राहत रही।

IGI एयरपोर्ट पर बम की अफवाह फैलाने वाला आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली पुलिस ने आइजीआई एयरपोर्ट को धमकी देनेवाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एक बयान में कहा हम लोगों को आश्वस्त करते हैं कि सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। हम सभी को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना अधिकारियों को देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

पश्चिमी दिल्ली। टीवी पर उड़ानों में बम की खबर देखने के बाद उत्तम नगर इलाके के एक युवक ने भी सोशल मीडिया पर बम की शूटी अफवाह फैला दी। उसे लग रहा था कि वह ऐसा करके फेमस हो जाएगा, लेकिन पुलिस ने उसे 24 घंटे में ही पकड़ लिया। आरोपित की पहचान उत्तम नगर के राजापुरी के शुभम उपाध्याय के रूप में हुई है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार रात को इंटरनेट मीडिया के माध्यम से आइजीआई एयरपोर्ट को उड़ान में बम की धमकी दी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन में आई और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया। प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान बम की सूचना अफवाह निकली।

ध्यान आकर्षित करने के लिए आरोपी ने उठाया कदम
धमकी उत्तम नगर के शुभम उपाध्याय नाम के खते से भेजी गई थी। तफ्तीश स्कूल छोड़ने वाले आधर पर आरोपित को राजापुरी से पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपित ने बताया कि उसने टीवी पर इसी तरह की खबर देखने के बाद अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा किया। उपाध्याय 12वीं पास है और बैरोजगार है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा, "हम लोगों को आश्वस्त करते हैं कि सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। हम सभी को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना अधिकारियों को देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।"

छत्तीसगढ़ से एक किशोर हिरासत में
बता दें, 16 अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से 17 वर्षीय स्कूल छोड़ने वाले एक लड़के को 14 अक्टूबर को चार फ्लाइट्स को धमकी देने के आरोप में हिरासत में लिया था। ऐसे को लेकर एक दोस्त के साथ विवाद के बाद किशोर ने कथित तौर पर उसके नाम से एक एक्स हैडल बनाया और उसे फंसाने के लिए धमकियां दी थीं।

प्रदूषण के विरुद्ध हेड बॉर्डर तिहाड़ जेल के नेतृत्व में अभियान

सुषमा रानी

नई दिल्ली। हर साल की तरह इस साल भी योगेंद्र कुमार मानंद पशु कल्याण प्रतिनिधि (भारतीय पशु कल्याण बोर्ड) एवं हेड वार्डर तिहाड़ जेल के नेतृत्व में प्रदूषण के विरुद्ध अभियान की शुरुआत सर्वोदय कन्या विद्यालय राजौरी गार्डन में नई दिल्ली 27 जिसमें 1200 बच्चों ने भाग लिया, तथा गर्वनमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी टैगोर गार्डन में विश्व पशु कल्याण दिवस के अवसर पर पशु पक्षियों पर क्रूरता के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर बच्चों को जागरूक करने के लिए (प्रदूषण के मानव एवं पशु पक्षियों पर दुष्प्रभाव) विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया एवं पशु पक्षियों पर क्रूरता रकने के उपायनिबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग

लिया और उत्कृष्ट बच्चों प्रशस्ति पत्र दे कर सम्मानित किए, , इस मौके पर योगेंद्र कुमार ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदूषण हमारे द्वारा निर्मित समस्या है और इसका समाधान भी हमने ही खोजना होगा एवं इससे निजात पाने के लिए हम सब ने मिल कर कार्य करना होगा तथा पशुओं के भी कुछ कानूनी अधिकार हैं उनपर क्रूरता करने पर सजा भी मिल सकती है प्रधानाचार्य अंजु सरदाना के बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि पशु पक्षियों के बिना इस समाज की कल्पना नहीं कर सकते इसलिए हम सब ने उनको सुरक्षा प्रदान करनी होगी, इस अवसर पर बच्चों ने भी कविताओं के माध्यम से बच्चों को जागरूक किया तथा प्रधानाचार्यममता ओकरॉयने पृथ्वी को सुरक्षित करने के लिए प्रदूषण से कैसे मुक्ति पाये इस विषय पर बच्चों को विस्तार से समझाया



एवं तथा इस अवसर में बीके पांडे, इंद्र जीत चौधरी, जय नाथ देविंद्र माखीजा, सोनु, राम सोनी मानंद पशु कल्याण प्रतिनिधि तथा अनिल निवास यादव, अमन एनमल के अर देकर ने

भी बच्चों से प्रदूषण के विरुद्ध अभियान से जुड़ने की अपील की।

घर-घर संविधान की महिम के चलते मयूर विहार में लगा सेल्फी प्वाइंट

सुषमा रानी

नई दिल्ली। घर-घर संविधान। मुहिम के तहत दीप चंदेलिया ऑस्ट्रेलिया द्वारा दिल्ली में निगम पार्श्व बीना बालगुहेर के ऑफिस मयूर विहार फेस 1 में पीपल्स वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष शालिनी और आजाद ने संविधान का सेल्फी प्वाइंट लगाया जिसमें निगम पार्श्व बीना बालगुहेर वरिष्ठ समाज सेवा श्यामलाल बालगुहेर, ज्योती रोहिताश कुमार, निगम पार्श्व बंटी गौतम शामिल हुए।



पर्यटन क्षेत्र में इजाफा तो औद्योगिक में हुई कमी, यमुना प्राधिकरण का ये है मास्टर प्लान

परिवहन विशेष न्यूज

मथुरा और वृंदावन देश ही नहीं बल्कि दुनिया में धार्मिकता और आध्यात्मिकता के लिए फेमस है। हर साल करोड़ों लोग यहां पर दर्शन के लिए आते हैं। कृष्ण नगरी के तौर पर यह पूरी दुनिया में विख्यात है। अब इसको देखते हुए यमुना प्राधिकरण ने फेज दो में औद्योगिक क्षेत्र को कम कर दिया है जबकि पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ोतरी की है। पढ़ें एक क्लिक में पूरी जानकारी।

ग्रेटर नोएडा। कृष्ण नगरी के तौर पर दुनिया में विख्यात मथुरा वृंदावन में पर्यटन के लिए असीम संभावनाएं हैं। हर साल लाखों लोग धार्मिक, आध्यात्मिक यात्रा के लिए मथुरा वृंदावन पहुंचते हैं। करोड़ों रुपये का राजस्व मिलता है। मथुरा में पर्यटन की संभावनाओं को फायदा उठाने के लिए यमुना प्राधिकरण ने हेरिटेज सिटी परियोजना तैयार की है।

पर्यटन गतिविधि का मुख्य केंद्र होगा। इसलिए प्राधिकरण ने अपने फेज दो के मास्टर प्लान 2031 को संशोधित करते हुए पर्यटन के लिए आरक्षित क्षेत्र को दो गुना से अधिक कर दिया है। औद्योगिक श्रेणी के क्षेत्रफल में तकरीबन पचास प्रतिशत की कटौती की गई है।

मथुरा में अपनी तक पर्यटन के लिए प्राचीन मंदिरों के अलावा पौराणिक महत्व से जुड़ी धरोहर ही मौजूद हैं। दुनिया भर से मथुरा आने वाले पर्यटक मंदिरों व पौराणिक धरोहरों के दर्शन के बाद लौट जाते हैं, इसलिए मथुरा जिले में सेवा सेक्टर का खास विकास नहीं हो पाया है।

753 एकड़ में विकसित होगा हेरिटेज सिटी
एन खामियों को दूर करते हुए पर्यटकों को अधिक से अधिक समय तक मथुरा क्षेत्र में रोकने के लिए हेरिटेज सिटी परियोजना तैयार की गई है। एनएच 44 से बांके बिहारी मंदिर तक 14 किमी लंबा मार्ग बनाकर 753 एकड़ में हेरिटेज सिटी



विकसित होगा। पर्यटकों को धार्मिक के अतिरिक्त आध्यात्मिक, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, स्थानीय उत्पाद की खरीदारी के अलावा ठहरने के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पर्यटन को केंद्र में रखकर ही प्राधिकरण ने यह परियोजना की है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डा. अरुणवीर सिंह का कहना है कि मथुरा में पर्यटन उद्योग के लिए असीम संभावनाएं हैं, लेकिन उनका ठीक तरह से दोहन नहीं किया गया है। रोजगार सृजन के लिए यह अच्छा जरिया बन सकता है।

इसलिए राया अर्बन सेंटर के नियोजन में पर्यटन को मुख्य केंद्र में रखा गया है। उद्योग के सापेक्ष पर्यटन को प्राथमिकता दी गई है। मथुरा पर्यटकों के लिए केंद्र बन सके। अधिक से अधिक समय तक पर्यटक मथुरा में ठहरेंगे तो इसका सीधा फायदा राजस्व बढ़ाने में मिलेगा।

फेज दो के संशोधित मास्टर प्लान में पर्यटन से संबंधित संरचनात्मक ढांचा विकसित करने के लिए आरक्षित क्षेत्र में बढ़ाया गया है। पूर्व में पर्यटन के लिए आरक्षित क्षेत्र 731.3 हे. था, जो अर्बन सेंटर के कुल क्षेत्रफल का 7.8 प्रतिशत था। इसे बढ़ाकर 1520.51 हे. किया गया है, यह कुल

क्षेत्रफल का 13 प्रतिशत हो गया है। रिवर फ्रंट भी पर्यटन क्षेत्र के विस्तार का ही हिस्सा है। इसे भी 109.7 प्रतिशत से बढ़ाकर 505.65 हे. किया गया है।

उद्योग के लिए आरक्षित क्षेत्रफल में कटौती की गई है। 1882.7 हे. के सापेक्ष इसे 853.46 हे. किया गया है। मिश्रित भूमि उपयोग 238.3 हे. से बढ़ाकर 301.44 हे. हुआ है। यह पूर्व के सापेक्ष 0.9 प्रतिशत अधिक हो गया है।

राया अर्बन सेंटर

- फेज दो मास्टर प्लान 2031
- श्रेणी आरक्षित क्षेत्रफल कुल क्षेत्र का प्रतिशत
- पर्यटन विकास 731.3 हे. 7.8
- रिवर फ्रंट 109.7 हे. 1.2
- मिश्रित 1882.7 हे. 20.1
- मिश्रित भू उपयोग 238.3 हे. 2.5

संशोधन के बाद

- श्रेणी आरक्षित क्षेत्रफल कुल क्षेत्र का प्रतिशत
- पर्यटन विकास 1520.51 हे. 13
- रिवर फ्रंट 505.65 हे. 4.34
- उद्योग 853.46 हे. 7.32
- मिश्रित भू उपयोग 301.44 हे. 2.59

टेली को लेकर पार्षद और वकील भिड़े, जमकर मारपीट

गाजियाबाद के अर्थला में शुक्रवार देर रात खली को लेकर स्थानीय पार्षद और अधिवक्ता पक्ष भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है। घटना के बाद मौके पर पुलिस बल मौजूद है ताकि फिर से कोई ऐसी मारपीट की घटना हो जाए। मामले में पुलिस जांच कर रही है।

गाजियाबाद। गाजियाबाद जिले के कोतवाली क्षेत्र के अर्थला में शुक्रवार देर रात खली को लेकर स्थानीय पार्षद और अधिवक्ता पक्ष भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दो समुदाय से जुड़ा मामला होने की सूचना पर भारी पुलिस मौके पर पहुंचा। पुलिस की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तीन लोगों को हिरासत में ले लिया है। शुक्रवार रात को साहिबाबाद कोतवाली क्षेत्र के अर्थला में टेली हटाने को लेकर स्थानीय पार्षद मनोज पाल और अधिवक्ता शमशाद सिद्दीकी में विवाद हो गया। दोनों पक्ष आमने सामने आगे। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट। मारपीट के दौरान अफरातफरी मच गई। दुकानदारों ने अपनी दुकानों बंद कर दीं।

पार्षद सहित तीन लोग हिरासत में
सूचना पर सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद रजनीश उपाध्याय, थाना प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पार्षद सहित तीन लोगों को हिरासत में लिया गया।

पुलिस ने क्या कहा
सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद रजनीश कुमार उपाध्याय ने बताया कि टेली हटाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था जिसके चलते मारपीट हुई। पुलिस की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है। अन्य की तलाश में दखिना दी जा रही है। एतिहातन मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है।

त्योहारों को लेकर बाजार गुलजार
त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। बाजार गुलजार होने लगे हैं। लोगों की भीड़ बाजारों में खरीदारी के लिए पहुंचने लगी है। सजावटी सामान, मिठाई, कपड़ों की दुकानों पर लोगों की भीड़ दिख रही है। बाजारों में स्टाल लगने शुरू हो गए हैं। रंग-बिरंगी लाइटों से दुकानें सजी हैं। बाजारों में हर्ष का माहौल है। व्यापारियों को त्योहारी सीजन में अच्छा व्यापार रहने की उम्मीद है।

बढ़ती हैं आपराधिक घटनाएं, पुलिस भी अलर्ट
भीड़ बढ़ने पर बाजारों में आपराधिक घटनाएं ना हो, इसके लेकर पुलिस भी अलर्ट हो गई है। बाजारों में पुलिस कार्रमियों के ड्यूटी प्वाइंट बनाए गए हैं। अगले हफ्ते धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजन व भाईदूज है। त्योहारों को लेकर लोगों में उत्साह है, जो बाजारों में बढ़ रही भीड़ से दिख रहा है। कस्बा रोड, गुरुद्वारा रोड, रुकमिणी मार्केट, गोविंदपुरी, निवाड़ी रोड समेत शहर के मुख्य बाजारों में त्योहारों की तैयारियां शुरू हो गई हैं।

व्यापारियों ने स्टॉक जमा कर लिया है। बाजारों में सजावटी सामान व लाइटों के स्टॉल लग चुके हैं। लोग यहां खरीदारी के लिए पहुंचने शुरू हो गए हैं।



नोएडा की ये 6 सड़कें होंगी मॉडल, डिजाइन तैयार; 100 करोड़ किया जाएगा खर्च

नोएडा। नोएडा शहर की छह सड़क को मॉडल रोड के रूप में विकसित किया जाएगा। इनको विकसित करने के लिए करीब 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इनका बजट और डिजाइन को सीईओ डॉ. लोकेश एम से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है।

इसी में एक उद्योग मार्ग को मॉडल रोड बनाने की प्रगति रिपोर्ट बोर्ड में प्रस्तुत की जाएगी। इन सभी पांच रोड को छह माह में मॉडल रोड के रूप में विकसित किया जाएगा। यह कार्य अलग कंपनियों करेगी।

दिल्ली बॉर्डर से स्टेडियम क्रॉसिंग तक की रोड होगी मॉडल
जोनल रोड नंबर -8 में दिल्ली बॉर्डर से स्टेडियम क्रॉसिंग तक की रोड को मॉडल बनाया जाएगा। इसकी लंबाई 1350 मीटर है। इसके लिए 28 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

यहां 2 मीटर चौड़ा फुटपाथ, लो हाइट सेंट्रल वर्ज, विद्युत सुंदरीकरण, इलेक्ट्रिक डक्ट, आरसीसी ड्रेन, 50 सेमी की ग्रीन बेल्ट का निर्माण होगा। सेक्टर-2 व 3 के बीच सेक्टर-16 से सेक्टर-3 लेबर चौक तक इसकी लंबाई 500 मीटर। मॉडल बनाने में करीब 10.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यहां अंडर ग्राउंड वृटिलिटी, ग्रीन बेल्ट, इलेक्ट्रिक डक्ट का काम होगा।

सेक्टर-6 व 8 के बीच वसुंधरा इंक्लेव की ओर जाने वाला मार्ग को उद्योग मार्ग तक कुल लंबाई 500 मीटर लागत करीब 11.30 करोड़ यहां भी वृटिलिटीस अंडर ग्राउंड की जाएंगी।

डीएससी रोड इसे दो हिस्सों में मॉडल बनाया जाएगा। पहला बॉटैनिकल गार्डन से अट्टा पीर तक और दूसरा सेक्टर-16 से सेक्टर-15 तक इसका प्रस्तुतीकरण हो चुका है। एएसजेड से कुलेसरा बार्डर तक इसका सुंदरीकरण किया जाएगा। यहां भी सभी वृटिलिटीस को अंडर ग्राउंड किया जाएगा।

कंपनी को तीन माह में विकसित करना होगा मॉडल रोड
इस रोड को मॉडल बनाने के लिए 49 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह रोड नोएडा की सबसे व्यस्त रोड में शामिल है। इसलिए इसका स्ट्रक्चर डिजाइन भी खास तैयार किया गया है। ताकि आने-जाने वाले ट्रैफिक को यहां जाम न मिले। कंपनी को तीन माह में पूरी सड़क को मडल रोड के रूप में विकसित करनी होगी।

नोएडा में फ्लैट खरीददारों के लिए अच्छी खबर, रजिस्ट्री को लेकर आया नया नियम; बिल्डरों को आदेश जारी

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा में अपने घर का सपना देखने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। नोएडा प्राधिकरण की 215 वीं बोर्ड बैठक शनिवार को सेक्टर-6 स्थित कार्यालय में हुई। इसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश मनोज कुमार सिंह ने की। ग्रुप हाउसिंग विभाग में नए नियम को मंजूरी मिली है। बुकिंग की दस प्रतिशत राशि लेकर अब बिल्डरों को फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री करानी होगी।

नोएडा। नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority News) की 215 वीं बोर्ड बैठक मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को सेक्टर-6 स्थित कार्यालय में आयोजित हुई। अवस्थाना एवं औद्योगिक विकास विभाग प्रमुख सचिव अरविंद कुमार सागर, नोएडा प्राधिकरण सीईओ डा लोकेश एम।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) सीईओ एनजी रवि कुमार, यमुना प्राधिकरण सीईओ डा अरुणवीर सिंह, गौतमबुद्धनगर जिलाधिकारी



मनीष कुमार वर्मा मौजूद रहे। बैठक में 27 प्रस्तावों को रखा गया, जिन पर बड़े स्तर पर चर्चा हुई। इस दौरान अमिताभकांत कमेटी की सिफारिश के तहत बिल्डरों को दी गई राहत पैकेज के बारे में प्रगति रिपोर्ट को देखा गया। जिसमें नोएडा प्राधिकरण सीईओ लोकेश एम ने बताया कि 22 अक्टूबर 2024 तक 1643 रजिस्ट्रियां कराई गईं। जिन बिल्डरों ने 25 प्रतिशत पैसा जमा करने के लिए हामी भरी है, उनसे पूरा पैसा लेकर शेष रजिस्ट्री कराई जाए। फ्लैट खरीदारों को मालिकाना हक और शासन को स्टॉप ड्यूटी के जरिये से राजस्व मिले। इसके लिए रेरा अधिनियम 2016 के



सेक्शन 13 को अनुमोदित किया गया। इसके तहत फ्लैट खरीदार बिल्डर को फ्लैट की कुल कीमत का 10 प्रतिशत राशि देकर बिल्डर द्वारा प्रॉपर्टी की वैल्यू के अनुसार स्टॉप ड्यूटी पे करते हुए एप्रीमेंट-टू-सेल या बिल्डर बायर्स अनुबंध लागू कर उपाय निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री कराएगा। ओसी जारी होने के बाद बिल्डर द्वारा फ्लैट खरीदार की सूची के साथ रजिस्टर्ड एप्रीमेंट-टू-सेल / बिल्डर बायर्स एप्रीमेंट की प्रति साथ में प्रस्तुत की जाएगी। प्राधिकरण, बिल्डर एवं फ्लैट खरीदार के पक्ष में त्रिपक्षीय लीड डीड की जाएगी। इसके बाद खरीदार को फ्लैट व दुकान पर कब्जा दिया जाएगा।

यह नया नियम ग्रुप हाउसिंग के लिए लागू किया गया।
दो परियोजनाओं पर को डेवलपर को मिली अनुमति
शासनदेश 21 दिसंबर 2023 के क्लज 9, 20 एवं 21 (बी) के तहत आर्वाटियों के अनुरोध पर भूखंड संख्या जीएच-01/ सी सेक्टर-168 नोएडा के आवंटी बिल्डर सनवर्द रेजीडेंसी प्राइवेट लिमिटेड परियोजना को पूरा करने के लिए निम्बस प्रोजेक्ट लिमिटेड को सह डेवलपर व भूखंड संख्या जीएच-01, सेक्टर-115 की परियोजना में थीम कांटेटी प्राइवेट लिमिटेड को डेवलपर नियुक्त किया गया है। इससे न

केवल परियोजनाएं पूर्ण कर फ्लैट खरीदार को फ्लैट मिलेंगे, बल्कि नोएडा प्राधिकरण को बकाया मिलेगा।

बकाया मिलेगा को 1578 करोड़ का अंतिम नोटिस
प्राधिकरण संपत्तियों पर पेट्रोल पंप और बैंक किराये पर संचालित हो रही है। किराये के एवज में इन पर 1578.14 करोड़ रुपये का बकाया है। ऐसे सभी डिफॉल्टर को अंतिम नोटिस जारी कर बकाया वापस करने के लिए कहा गया है। अन्यथा की स्थिति में बिल्डिंग सील करने के निर्देश दिया गया।

डेटा सेंटर की जगह पर अब आईटी/आईटीईएस
राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा आईटी/आईटीईएस के भू-उपयोग भूखंड संख्या 02/099 सेक्टर-154 क्षेत्रफल 14867 वर्गमीटर और भूखंड संख्या 02/11 सेक्टर-154 क्षेत्रफल 14247 को डाटा सेंटर के लिए आवंटित करने के लिए बाय योजना निकाली गई लेकिन एक बार भी कंपनी नहीं आई। ऐसे में दोबारा से आईटी/आईटीईएस उपयोग करके दोनों भूखंडों का आवंटन किया जाएगा।

पीने योग्य शराब बनाम औद्योगिक शराब

सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच का ऐतिहासिक फैसला—34 साल पुराना अपना ही आदेश पलट दिया आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही राज्य सरकारों के लिए औद्योगिक शराब टैक्स के रूप में राज्यों को नया राजस्व स्रोत मील का पत्थर साबित होगा—एडवोकेट किशन सनमुखादास भावनानी गौदिया महाराष्ट्र

गौदिया - वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी की निर्भरता के बढ़ते दौर में जीवन का परिदृश्य ही बदल गया है। जहां एक ओर इससे लॉन्ग टर्म सकारात्मक फायदे हो रहे हैं वहीं दूसरी तरफ शराब तंबाकू सट्टा और सहित अनेक चलत तौर तरीके के व्यसन की ओर मानवीय जीव चला रहा है। तो तीसरी ओर इसका व्यापार व्यवसाय करने वालों और राज्य सरकारों को भी मोटी आमदनी हो जाती है विशेष रूप से राज्य सरकारों को शराब से मोटा राजस्व प्राप्त होता है, यही कारण है कि पिछली बार कोविड अवधि में जहां सारा देश लॉकडाउन था वही सबसे पहले शराब विक्री को ही अनुमति दी गई थी, याने वही राजस्व का चक्कर था, आज हम शराब पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बुधवार दिनांक 23 अक्टूबर 2024 को शाम संवैधानिक पीठ ने अपने ही 34 साल पुराने आदेश को पलट दिया और औद्योगिक शराब पर राज्य सरकारों को कर नीति बनाने या इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया है। हम कुछ अवधि से कुछ दशकों से सुनते आ रहे हैं कि जहरीली शराब से इतने मरे उतने मरे अभी-अभी हमने तमिलनाडु बिहार सहित कुछ राज्यों में जहरीली शराब पीने से बहुत लोगों की मौत का समाचार सुना था स्वाभाविक है औद्योगिक शराब का दुरुपयोग हुआ होगा, इसलिए ही राज्यों ने 34 साल की लड़ाई करमशकत के बाद फैसला उनके हक में आया है, इन पर कानून बनाने से अधिक औद्योगिक शराब पर मोटी टैक्स लगाने से राजस्व में भारी वृद्धि करने का फंडा है, क्योंकि अनेक राज्य सरकारी रेवेडियों के कारण आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों

की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला दिया है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही राज्य सरकारों के लिए औद्योगिक शराब पर टैक्स के रूप में राज्यों को नया राजस्व स्रोत मील का पत्थर साबित होगा। साधियों बात अगर हम पीने योग्य शराब बनाम औद्योगिक शराब पर 9 जजों की बेंच द्वारा 23 अक्टूबर 2024 को दिए गए जजमेंट की करें तो, 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इंडस्ट्रियल शराब के अधिकार को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें पुष्टि की गई कि राज्यों के पास इस मामले पर कानून बनाने का अधिकार है। केरल, महाराष्ट्र पंजाब और यूपी जैसे राज्य इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की शरण में थे, उनकी दलील थी कि जिस तरह इसका उपयोग किया जा रहा है, उसको देखते हुए राज्य सरकारें चुप नहीं बैठ सकती क्योंकि इनके उपयोग से जहरीली शराब भी बनाई जा रही है और मौते हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला 9 जजों की खंडपीठ ने किया। ये फैसला 8:1 बहुमत से सुनाया गया फैसले में इसे नशीली शराब के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस फैसले ने 1990 के पुराने फैसले को पलट दिया कि, जबकि इस पॉवर केंद्र सरकार तक सीमित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडस्ट्रियल शराब पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों का है, इसे छोना नहीं जा सकता है। 19 जजों की बेंच ने 7 जजों की बेंच के फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि इंडस्ट्रियल शराब को रेगुलेट करने का अधिकार केंद्र के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है इंडस्ट्रियल अल्कोहल यानि औद्योगिक अल्कोहल का मसला केंद्र से ज्यादा राज्य सरकारों का है, लिहाजा वो इस पर कानून बनाने का अधिकार रखती हैं। इंडस्ट्रियल अल्कोहल को औद्योगिक शराब भी कह सकते हैं, इसे विकृत अल्कोहल भी कह सकते हैं, ये चूँकि इलेनॉल का शुद्धता वाला रूप में है, लिहाजा इसका इस्तेमाल मानव उपभोग के लिए नहीं होता, ये पीते ही स्वास्थ्य को खराब कर सकती है और अस्पताल पहुंचा सकती है। ये जहरीली शराब जैसा काम भी

करती है, असस में सुप्रीम कोर्ट ने 8:1 की बहुमत से फैसला सुना दिया है कि राज्य सरकार के पास भी औद्योगिक शराब को भी रेगुलेट करने की ताकत राज्य सरकारों के पास रहने वाली है, इसे उनसे छीना नहीं जा सकता है। बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि कानून की शक्ति और नशीली शराब के उत्पाद दोनों शामिल रखे जाएंगे। इसका मतलब यह है कि नशीली शराब पर भी कानून बनाने का अधिकार राज्य का रहने वाला है। साधियों बात अगर हम पीने योग्य शराब व औद्योगिक शराब को समझने की करें तो, क्या है नशीली शराब की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सातवीं अनुसूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 8 में “नशीली शराब” शब्द में औद्योगिक शराब शामिल है, जो बताता है कि ये अगर मनुष्यों द्वारा उपयोग में लाई जाए तो जहर जैसा काम करती है, बहुमत की राय ने इस बात पर जोर दिया कि “नशीली” का अर्थ हानिकारक या जहरीले पदार्थों से भी हो सकता अल्कोहल कितनी तरह की होती है। शराब मुख्य तौर पर दो तरह की होती है औद्योगिक अल्कोहल यह आमतौर पर आइसोप्रोपिल अल्कोहल (आइसोप्रोपेनॉल) या विकृत अल्कोहल (एडिटिव के साथ इथेनॉल) होती है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल की केमिकल संरचना सी₃H₈O होती है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से औद्योगिक सेंटिंग में सफाई और कीटाणुनाशक के लिए किया जाता है दूसरी औद्योगिक अल्कोहल इथेनॉल यानि सी₂H₅ओ होता है, जिसका उपयोग अक्सर जहरीली शराब बनाने में किया जाता है। उपयोग की जाने लायक अल्कोहल-यह मुख्य रूप से इथाइल अल्कोहल (इथेनॉल) है जिसका उपयोग मनुष्यों द्वारा किया जाता रहा है। बीयर, वाइन और स्प्रीट जैसे मादक पेय पदार्थों में इसी के घटक होते हैं। इथेनॉल खो खमीर द्वारा शर्करा के किण्वन के माध्यम से बनाया जाता है औद्योगिक शराब का जहरीलाप आइसोप्रोपिल और विकृत शराब दोनों ही अगर पीये जाएं तो जहर जैसा काम

पीने योग्य बनाम औद्योगिक शराब



करते हैं सेवन से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, मसलन-पेट और आंतों में बुरी तरह जलन-नर्वस सिस्टम पर बुरी तरह असर-छोटी मात्रा से भी संभावित घातक परिणाम, आंखें जल सकती हैं पागलपन, मौत भी-औद्योगिक शराब के लगातार सेवन से लीवर और किडनी को नुकसान हो सकता कोमा का जोखिम, क्या इथेनॉल हमेशा जहरीला होता है — नहीं ऐसा नहीं है। इथेनॉल उच्च खुराक हमेशा जहरीली होती है, लेकिन तय सीमा सेवन के लिए सुरक्षित है शरीर इथेनॉल को तब पचा सकता है, जब जिम्मेदारी से इसका सेवन किया जाए, तब इसके हानिकारक प्रभाव नहीं होंगे। साधियों बात अगर हम इस केस को समझने की करें तोकेस यह था कि क्या राज्य सरकारों के पास इंडस्ट्रियल अल्कोहल की सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग को रेगुलेट और कंट्रोल

करने की शक्ति है या नहीं। इंडस्ट्रियल अल्कोहल का उपयोग फार्मास्यूटिकलस, कीटाणुनाशक, रसायन और यहां तक कि जैव ईंधन के निर्माण में होता है। सुप्रीम कोर्ट बोला- औद्योगिक शराब पर टैक्स का अधिकार राज्य के पास औद्योगिक शराब संविधान की लिस्ट II की एंटी 8 के तहत नशीली शराब की परिभाषा के तहत आती है, जिससे राज्यों को इसके उत्पादन को विनियमित करने और टैक्स लगाने का अधिकार मिलता है। औद्योगिक शराब पर कानून बनाने की शक्ति की शक्ति छीनी नहीं जा सकती। साल 2010 में यह केस 9 जजों की बेंच में ट्रांसफर हुआ था। इस साल अप्रैल में इस केस में 6 दिन लगातार सुनवाई हुई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज 9 जजों की बेंच ने 8:1 के बहुमत से फैसला सुनाया। जस्टिस बीवी नागरल्ला ने फैसले का विरोध किया। इंडस्ट्रियल अल्कोहल इथेनॉल का अशुद्ध रूप है। आमतौर पर सॉल्वेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये लोगों के पीने के लिए नहीं होती। अनाधिकृत उपभोग से बचाने के लिए, इंडस्ट्रियल शराब में उल्टी पैदा करने वाला पदार्थ मिलाकर भी बेचा जाता है। यथाचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि इंडस्ट्रियल शराब पर टैक्स लगाने की शक्ति महत्वपूर्ण है। ये राज्यों की आय का एक महत्वपूर्ण जरिया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यदि औद्योगिक शराब को विनियमित करने की शक्ति केंद्र के पास चली जाती है, तो औद्योगिक शराब की अवैध खपत से निपटने के मामले में उनके हाथ बंधे रहेंगे। यथाचिकाकर्ताओं ने अदालत को औद्योगिक शराब के उत्पादन की तकनीकी प्रक्रिया के माध्यम से यह भी समझाने की कोशिश की कि सभी शराब “नशीली” होती है चाहे पीने योग्य हो या नहीं। केंद्र ने तर्क दिया कि औद्योगिक शराब को विनियमित करने की शक्ति हमेशा उनकी रही है। स्टेट लिस्ट की एंटी 8 का उस शराब से कोई लेना-देना नहीं है जो पीने योग्य नहीं है। इंडस्ट्रियल अल्कोहल केस- 7 जजों की बेंच का फैसला पलटा सुप्रीम कोर्ट ने

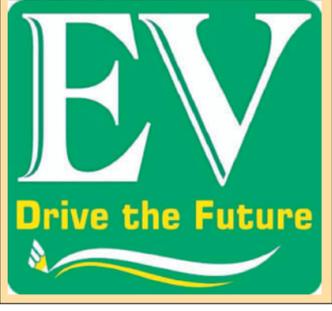
कहा- कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास, इसे नहीं छीना जा सकता वर्तमान मामले को 2007 में नौ जजों की पीठ को भेजा गया और यह उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (आईटीआर अधिनियम) की धारा 18 जी की व्याख्या से संबंधित है। धारा 18 जी केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने की अनुमति देती है कि अनुसूचित उद्योगों से संबंधित कुछ उत्पाद निष्पक्ष रूप से वितरित किए जाएं और उचित मूल्य पर उपलब्ध हों। वे इन उत्पादों की आपूर्ति, वितरण और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करके ऐसा कर सकते हैं। हालांकि, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 33 के अनुसार, राज्य विधानमंडल के पास संघ के नियंत्रण वाले उद्योगों और इसी तरह के आयोजित सामानों के व्यापार, उत्पादन और वितरण को विनियमित करने की शक्ति है। यह तर्क दिया गया कि सिंथेटिकस एंज के केमिकल लिमिटेड बनाम यूपी राज्य में सात जजों की पीठ राज्य की समवर्ती शक्तियों के साथ धारा 18 जी के हस्तक्षेप को संबंधित करने में विफल रही थी। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि पीने योग्य शराब बनाम औद्योगिक शराब सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच का ऐतिहासिक फैसला- 34 साल पुराना अपना ही आदेश पलट दिया, आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही राज्य सरकारों के लिए औद्योगिक शराब टैक्स के रूप में राज्यों को नया राजस्व स्रोत मील का पत्थर साबित होगा।

संकलनकर्ता लेखक - कर विशेषज्ञ स्तंभकार अंतर्राष्ट्रीय लेखक चितक कवि एी ए (ए टी सी) एडवोकेट किशन सनमुखादास भावनानी गौदिया महाराष्ट्र



- सौजन्य -

ईवी ड्राइव द फ्यूचर



परिवहन विशेष न्यूज

पटना सहित बिहार के विभिन्न जिलों में तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहनों के कारण सरकार तेजी से चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए जगह का सर्वे कर रही है। अगले साल करीब 1000 से अधिक चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। सरकारी के साथ-साथ प्राइवेट कंपनियों ने चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सहमति दिखाई है। विभिन्न स्टेक होल्डर्स एवं अन्य कंपनियों के प्रतिनिधियों ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का आश्वासन दिया। परिवहन विभाग

ने 1000 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के विभिन्न पेट्रोल पंप और अन्य जगहों पर 300 से अधिक ईवी चार्जिंग की सुविधा है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों और एजेंसियों के बीच तालमेल बनाकर कार्य किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक निश्चित दूरी पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, ताकि लंबी दूरी की यात्रा के दौरान ईवी उपयोगकर्ताओं को कोई असुविधा न हो। इसके साथ ही शहर के विभिन्न मार्गों, पेट्रोल पंपों, बस टर्मिनल, बस डिपो, स्कूल कॉलेज

इत्यादि जगहों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में राज्य के विभिन्न पेट्रोल पंप और अन्य जगहों पर 300 से अधिक ईवी चार्जिंग की सुविधा है।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के सभी पुलों के नीचे के खाली जगह में चार्जिंग लगाने के लिए पटना नगर निगम को प्राधिकृत किया गया। पटना नगर आयुक्त को इस ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है कि नगर निगम द्वारा अपने स्तर से भी पटना की महत्वपूर्ण जगहों को पार्किंग के लिए चिह्नित करते हुए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।



सीईएसएल ने फरीदाबाद में ईवी चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों के लिए बोलियां की आमंत्रित

परिवहन विशेष न्यूज

कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) ने फरीदाबाद में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की एक महत्वपूर्ण पहल में भाग लेने के लिए चार्जिंग प्वाइंट ऑपरेटर्स (सीपीओ) को आमंत्रित करते हुए एक निविदा शुरू की है।

यह निविदा नगर निगम फरीदाबाद (एमसीएफ) के तहत चयनित स्थानों पर 'इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों' की खरीद, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग और संचालन और रखरखाव' पर केंद्रित है। बूम (बिल्ड, ओन, ऑपरेंट और मटेमेंट) मॉडल के तहत, परियोजना आवश्यक चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को सक्षम करके शहर के भीतर टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देना चाहती है।

सीईएसएल ने एन-ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से एकल-चरणीय, दो-लिफ्टाफ प्रणाली स्थापित की है। इच्छुक बोलीदाता 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, 2024 तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं।

भाग लेने के लिए बोलीदाताओं को 15,000 रुपये का गैर-वापसी योग्य निविदा शुल्क अदा करना होगा तथा 2,12,000 रुपये की बयाना राशि (ईएमडी) जमा करनी होगी।

23 अक्टूबर, 2024 को निर्धारित प्री-बिड कॉन्फ्रेंस वचुअली आयोजित की



जाएगी। सीईएसएल ने 30 अक्टूबर को तकनीकी-व्यावसायिक बोलियाँ खोलने की योजना बनाई है, जिसमें सभी बोलियाँ प्रस्तुत तिथि से 180 दिनों की अवधि के लिए वैध होंगी। सीईएसएल की परियोजना योजना चयनित बोलीदाताओं को साइट व्यवहार्यता का आकलन करने, बिजली कनेक्शन सुरक्षित करने, उपकरण स्थापित करने और सभी परिचालन और रखरखाव कार्यों का संचालन करने में एक व्यापक भूमिका सौंपती है।

इस स्थापना में धीमी और तेज दोनों तरह के ईवी चार्जर के साथ-साथ बैटरी स्वैपिंग स्टेशन शामिल होंगे, जिसके वित्तपोषण और रखरखाव के लिए बोलीदाता जिम्मेदार होंगे। साइट के मूल्यांकन के लिए मुख्य विनिर्देशों में

पर्याप्त पार्किंग स्थान और वाहनों का सुचारू आवागमन सुनिश्चित करना शामिल है, जिससे उन्हें दोपहिया वाहनों से लेकर बसों तक विभिन्न प्रकार के ईवी के लिए सुलभ बनाया जा सके।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक साइट को विद्युत मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा, जिसमें उपयोगकर्ता की सुविधा को अधिकतम करने के लिए उच्च-फुटफॉल वाले क्षेत्रों और आवासीय समुदायों से निकटता शामिल है। बोली दाताओं को यह निर्धारित करने के लिए सभी सात प्रस्तावित स्थानों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने की भी आवश्यकता होगी कि क्या वे परियोजना विनिर्देशों के अनुरूप हैं।

बोलीदाताओं को नए बिजली कनेक्शन

स्थापित करने की वित्तीय जिम्मेदारी उठानी होगी, तथा सीईएसएल के नाम से भुगतान और मासिक बिजली बिल का प्रबंधन संबंधित सीपीओ द्वारा किया जाएगा।

अन्य दायित्वों में परिचालन लॉग बनाए रखना, मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) मानकों के अनुसार आवश्यक भागों की खरीद करना, तथा सभी आवश्यक

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए निविदा में निर्दिष्ट समय-सीमा में यह रेखांकित किया गया है कि संपूर्ण स्थापना और परिचालन प्रक्रिया - जिसमें खरीद, आपूर्ति, परीक्षण, कमीशनिंग और रखरखाव शामिल है - को लैटर ऑफ अवार्ड (LoA) जारी होने के चार महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

बोलीदाता को कनेक्शन विच्छेदन से होने वाले किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नुकसान के लिए भी जिम्मेदार उतराया जाएगा, जिसमें भुगतान सुरक्षा पुनः प्रस्तुत करने में होने वाली देरी भी शामिल है, जिसे सीईएसएल एक अर्जित वित्तीय लाभ के रूप में मानेगा और ठेकेदार को 30 दिनों के भीतर इसका चालान देगा।

इस पहल का उद्देश्य हरित परिवहन नेटवर्क को बढ़ावा देना है जो फरीदाबाद को टिकाऊ शहरी गतिशीलता समाधानों की ओर ले जाएगा। इच्छुक बोलीदाता CESL ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट पर परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या किसी भी स्पष्टीकरण के लिए CESL के अनुबंध विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

इंडिया में हिट लेकिन विदेशों में नहीं है इन 5 कारों की मांग

भारतीय बाजार में हर महीने लाखों की संख्या में वाहनों की बिक्री की जाती है। साथ ही भारत में बनाई गई कारों का हर महीने कई देशों को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी कौन सी कारें हैं जिनको भारत में तो काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन विदेशों में इन कारों की मांग काफी कम है। आइए जानते हैं।

Maruti Wagon R की भी मांग कम

भारत में बनी मारुति वैगन आर काफी ज्यादा पसंद की जाने वाली कार है। देश में हर महीने इसकी हजारों यूनिट्स की बिक्री होती है। लेकिन बाते महीने इसकी सिर्फ 29 यूनिट्स का ही एक्सपोर्ट किया गया। मारुति की इस गाड़ी 9 September 2023 के दौरान 73 यूनिट्स को विदेश भेजा गया था।

लिस्ट में शामिल हुई

Maruti XL6

छह सीटों वाली एमपीवी के तौर पर भारत में Maruti XL6 को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक मेड इन इंडिया इस एमपीवी की बाते महीने सिर्फ 54 यूनिट्स का ही एक्सपोर्ट किया गया है। ईथर ऑन ईथर बेसिस के मुताबिक पिछले साल September महीने में इसकी 128 यूनिट्स को एक्सपोर्ट किया गया था।

बाते महीने Honda

Amaze की मांग में कमी आई

जापानी हर निर्माता Honda की ओर से Compact Sedan Car सेगमेंट में Honda Amaze को भारत में ऑफर किया जाता है। हर महीने यहाँ इसकी हजारों यूनिट्स की बिक्री होती है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक बाते महीने इसकी सिर्फ 60 यूनिट्स का ही एक्सपोर्ट किया गया है।

एक्मा मोबिलिटी फाउंडेशन ने भारतीय ऑटो कंपोनेंट्स में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट्स के साथ की साझेदारी

परिवहन विशेष न्यूज

ऑटोमोटिव कम्पोनेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की पहल, एक्मा मोबिलिटी फाउंडेशन ने भारत के ऑटो कम्पोनेंट उद्योग के लिए अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाने के लिए जर्मनी के फ्राउनहोफर-गोसेलशाफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस साझेदारी को नई दिल्ली में आयोजित 18वें एशिया-प्रशांत जर्मन बिजनेस सम्मेलन (एपीके 2024) के दौरान औपचारिक रूप दिया गया, जिसका उद्देश्य उद्योग-संचालित अनुसंधान और नवाचार के लिए एक नए चरण को बढ़ावा देना है, तथा इस क्षेत्र को कार्बन तटस्थता, परिपत्रता, सुरक्षा और पर्यावरणीय जिम्मेदारी की ओर बदलाव का समर्थन करना है।

एमएफ और फ्राउनहोफर के बीच सहयोग का उद्देश्य भारत के ऑटोमोटिव क्षेत्र में प्रौद्योगिकी, स्थिरता और उत्पाद नवाचार को बढ़ाना है। फ्राउनहोफर संस्थान भारतीय ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए नए उत्पाद विकास, प्रक्रिया नवाचारों और प्रतिस्पर्धी अनुसंधान एवं विकास पर केंद्रित

अनुसंधान अनुसंधान परियोजनाओं पर एमएफ के साथ मिलकर काम करेंगे। फ्राउनहोफर के विशेषज्ञ प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों में सुधार और संधारणीय उत्पादन विधियों को एकीकृत करने के लिए भारतीय ऑटोमोटिव कंपनियों के साथ जुड़ेंगे। इसके अतिरिक्त, संधारणीय उत्पादन और सड़क सुरक्षा को लक्षित करने वाली संयुक्त परियोजनाएं विकसित की जाएंगी, जो उद्योग-व्यापी अनुसंधान के लिए परिपत्र अर्थव्यवस्था सिद्धांतों और प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करेंगी।

एमएफ के निदेशक और जेके फेनर (इंडिया) के प्रबंध निदेशक विक्रमपति सिंघानिया ने इस साझेदारी को भारतीय ऑटो कंपोनेंट क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकास बताया। उन्होंने कहा कि अनुसंधान अनुसंधान में फ्राउनहोफर की विशेषज्ञता नवाचार को बढ़ावा देने, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने और भारत में टिकाऊ गतिशीलता समाधानों की ओर बदलाव का समर्थन करने में मदद करेगी।

एमएफ के निदेशक और सचिव विन्नी मेहता ने भारत के ऑटो कंपोनेंट क्षेत्र में अनुसंधान एवं



विकास क्षमताओं को बढ़ाने में इस सहयोग की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस साझेदारी से भारतीय कंपनियों को अनुसंधान अनुसंधान में फ्राउनहोफर की व्यापक विशेषज्ञता का लाभ उठाने में मदद मिलेगी, जिससे उन्हें

प्रतिस्पर्धी लागत पर नवाचार को बढ़ावा देते हुए अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में मदद मिलेगी। फ्राउनहोफर-गोसेलशाफ्ट, जो 76 शोध संस्थानों का संचालन करता है और जिसकी वैश्विक उपस्थिति महत्वपूर्ण है, जिसका वार्षिक

शोध बजट 3.4 बिलियन यूरो से अधिक है, अपने यातायात और परिवहन गठबंधन के माध्यम से सहयोग का नेतृत्व करेगा। 18 संस्थानों का यह समूह भारत में ऑटोमोटिव पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए विशेष अनुसंधान और

विकास सेवाएँ प्रदान करता है।

फ्राउनहोफर मुख्यालय में प्रतिस्पर्धी-पूर्व अनुसंधान और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के निदेशक और अनुभाग प्रमुख डॉ. जोहान फेकल ने गतिशीलता क्षेत्र में भारत और जर्मनी के बीच तालमेल पर जोर दिया। उन्होंने गतिशीलता मूल्य श्रृंखला में फ्राउनहोफर की विशेषज्ञता की ओर इशारा किया - सामग्री और विनिर्माण से लेकर गतिशीलता अवधारणाओं तक - और विनिर्माण और कुशल जनशक्ति में भारत की ताकत का उल्लेख किया।

फ्राउनहोफर ऑफिस इंडिया की निदेशक आनंदी अय्यर ने फ्राउनहोफर और भारत के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को स्वीकार करते हुए कहा कि फ्राउनहोफर ने 16 वर्षों तक भारतीय ऑटोमोटिव क्षेत्र के साथ सहयोग किया है, जिसमें ACMA एक प्रमुख भागीदार है। उन्होंने इस सहयोग के लिए आशा व्यक्त की, जिसका उद्देश्य भारत-विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करना, अवधारणाओं का प्रमाण तैयार करना और नवाचारों को बढ़ाना है, पारस्परिक लाभ के लिए जर्मन इंजीनियरिंग को भारतीय सरलता के साथ मिलाना है।

खराबी की जानकारी मिलने के बाद होंडा ने भारत में रिकॉल की 90 हजार से ज्यादा गाड़ियां, फ्री में ठीक करेगी खामी

परिवहन विशेष न्यूज

जापानी वाहन निर्माता Honda की ओर से भारतीय बाजार में सेडान और एसयूवी सेगमेंट में वाहनों को ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने हाल में ही अपनी हजारों कारों के लिए Recall को जारी किया है। कंपनी की ओर से किस्म की खराबी के बाद इनको बुलाया गया है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में कई बेहतरीन कारों को ऑफर करने वाली जापानी वाहन निर्माता Honda की ओर से अपनी हजारों कारों के लिए Recall को जारी किया गया है। कंपनी की ओर से किस तरह की खराबी की जानकारी मिलने के बाद किस्म की खराबी को वापस बुलाया गया है। जानकारी के मुताबिक कंपनी ने 92672 यूनिट्स के लिए Recall जारी किया है। इनमें से 90468 यूनिट्स में यह खराबी मिली है लेकिन कंपनी 2204 अन्य पुरानी कारों को भी बुलाकर उनके पार्ट्स भी बदलेगी।

यह भी पढ़ें- Upcoming Cars: दो Sedan and SUV सेगमेंट में जल्द



Honda ने जारी किया Recall मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापानी वाहन निर्माता होंडा मोटर्स की ओर से अपने वाहनों में गडबडी की जानकारी मिलने के बाद हजारों यूनिट्स को वापस बुलाया गया है। जानकारी के मुताबिक कंपनी ने 92672 यूनिट्स के लिए Recall जारी किया है। इनमें से 90468 यूनिट्स में यह खराबी मिली है लेकिन कंपनी 2204 अन्य पुरानी कारों को भी बुलाकर उनके पार्ट्स भी बदलेगी।

यह भी पढ़ें- Upcoming Cars: दो Sedan and SUV सेगमेंट में जल्द

लॉन्च होंगी चार कारें, कीमत रहेगी 10 लाख रुपये से कम

किस्म तरह की खराबी की मिली जानकारी

रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी को अपनी कारों के फ्यूल पंप में खराबी की जानकारी मिली है। जिसके बाद हजारों यूनिट्स के लिए रि कॉल जारी किया गया है। कंपनी के मुताबिक जिन कारों के लिए रि कॉल जारी किया गया है उनके फ्यूल पंप में खराब इंपेल्सर हो सकते हैं जिस कारण इंजन बंद हो सकता है या फिर उसे शुरू करने में परेशानी आ सकती है।

दिवाली 2024 के बाद इस तारीख को आएगी रॉयल इन्फिल्ड इंटर सेक्टर बीअर650, मिलेगा दमदार इंजन और फीचर्स

परिवहन विशेष न्यूज

दो पहिया वाहन निर्माता Royal Enfield की ओर से जल्द ही नई बाइक को लाने की तैयारी की जा रही है। बाइक के लॉन्च से पहले सोशल मीडिया पर नई बाइक का टीजर जारी किया गया है। इसे कब तक लॉन्च किया जा सकता है। इसमें किस तरह के फीचर्स और इंजन मिल सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में Royal Enfield की ओर से 350 से लेकर 650 सीसी की क्षमता की बेहतरीन बाइक्स को बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। कंपनी की ओर से Diwali 2024 के बाद एक और नई बाइक लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। लॉन्च से पहले सोशल मीडिया पर इसका टीजर भी जारी किया गया है। कंपनी किस बाइक को किस तारीख में लॉन्च करेगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

आएगी नई बाइक रॉयल एनफील्ड की ओर से भारतीय



बाजार में जल्द ही नई बाइक को लाने की तैयारी की जा रही है। कंपनी की ओर से 650 सीसी सेगमेंट में Interceptor Bear 650 को लाया जाएगा। लॉन्च से पहले सोशल मीडिया पर रॉयल एनफील्ड की ओर से इसका टीजर जारी कर दिया गया है।

क्या मिली जानकारी

टीजर से फिलहाल यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि किस तरह के फीचर्स के साथ बाइक को लाया जाएगा। लेकिन कंपनी ने यह जानकारी दे दी है कि इस बाइक को पांच

नंबर को लॉन्च किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इसमें कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाएगा।

कैसे होंगे फीचर्स

जानकारी के मुताबिक बाइक में अलॉय व्हील्स की जगह स्पोक व्हील दिए जाएंगे। आगे और पीछे के पहियों पर डिस्क ब्रेक मिलेगी। बाइक में ड्यूल चैनल एबीएस, एलईडी लाइट्स, राउंड शैप स्पीडोमीटर, स्क्रैम्बलर स्टाइल वाली सीट, यूएसडी फॉर्कस को दिया जाएगा।

कितना दमदार इंजन

रॉयल एनफील्ड की ओर से आने वाली नई बाइक में 648 सीसी की क्षमता का एयर/ऑयल कूल्ड इंजन दिया जाएगा। जिससे बाइक को 47 बीएचपी की पावर और 52.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। बाइक को 6स्पीड गियरबॉक्स के साथ लाया जाएगा। जिसके साथ 17 और 18 ईंच के पहिए दिए जाएंगे।

कितनी होगी कीमत

कंपनी की ओर से बाइक को लॉन्च करने के साथ ही सही कीमत की जानकारी दी जाएगी। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस बाइक को 3.50 लाख रुपये की संभावित एक्स शोरूम कीमत के आस-पास लॉन्च किया जा सकता है।

EICMA में भी आएगी नई बाइक्स

इटली के मिलान में होने वाले EICMA 2024 में भी रॉयल एनफील्ड की ओर से अपनी कई बाइक्स को पेश किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कंपनी की ओर से पहली इलेक्ट्रिक बाइक को भी पेश किया जाएगा। इसके अलावा भी कंपनी कई और बाइक्स को अपडेट के साथ लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।

घोड़े के कारोबार से हुई शुरुआत, अब फ्लाइट में है दफ्तर... जानिए वैक्सीन मैन के रोमांचक फैक्ट

परिवहन विशेष न्यूज

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला (Adar Poonawalla) Dharma Production में आधी हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। बता दें कि उन्हें वैक्सीनमैन के नाम से जाना जाता है। Dharma Production में आधी हिस्सेदारी खरीदने के बाद वह एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। हम आपको इस आर्टिकल में अदार पूनावाला और उनके परिवार से जुड़े कुछ रोचक बातों के बारे में बताएंगे।...

नई दिल्ली। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) के सीईओ एक बार फिर से चर्चा में आ गए। जी हाँ, माना जा रहा है कि वैक्सीनमैन के नाम से जाने वाले अदार पूनावाला (Adar Poonawalla) ने करण जोहर के Dharma Productions में आधी हिस्सेदारी खरीदी है। इस खबर के आने के बाद अब लोगों में काफी उत्सुकता है कि अदार पूनावाला का सफर कैसा रहा है। हम आपको इस आर्टिकल में अदार पूनावाला से जुड़े कुछ रोचक और खास बातों के बारे में बताएंगे।

सुर्खियों में रहता है पूनावाला फैमिली
पूनावाला फैमिली अपने लाइफ स्टाइल के कारण सुर्खियों में रहता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूनावाला परिवार ने साल 2023 में लंदन में 25,000 वर्गफीट में बना एकरकोनवे हाउस खरीदा था। यह हाउस उन्होंने 1446 करोड़ रुपये में खरीदा था। ऐसा माना जाता है कि यह घर लंदन की सबसे महंगी प्रॉपर्टी है।

अदार पूनावाला के पिता ने साल 2015 में 750 करोड़ रुपये में लिंकन हाउस खरीदा था, जो कि मुंबई में बरीच कैडी अस्पताल के पास स्थित है। यह लिंकन हाउस एक समय पहले अमेरिका का कर्मस्थल दूतावास था।

ब्रिटिश राज में आया था परिवार

पूनावाला का फैमिली पारसी है। वह 19वीं शताब्दी में पुणे आए थे। भारत की आजादी से पहले पूनावाला परिवार



कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते थे। लेकिन, पूनावाला की पहचान घोड़ों के कारोबार से हुआ। पूनावाला फैमिली में घोड़े का कारोबार अदार के दादा सोली पूनावाला ने शुरू किया। सोली पूनावाला रेंस के लिए घोड़े तैयार करते थे। इसी कारण अंग्रेज अधिकारी और व्यापारी सोली पूनावाला को जानते थे।

सेल्स विभाग से शुरू किया करियर
अदार पूनावाला ने इंग्लैंड से पढ़ाई पूरी की। उन्होंने लंदन के वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सीरम इंस्टीट्यूट के सेल्स विभाग से शुरू की। सीरम इंस्टीट्यूट में करीब 10 साल काम करने के बाद वह 2011 में सीरम ग्रुप के सीईओ बने।

अदार पूनावाला ने जैसे ही सीईओ का पद संभाला उन्होंने दो चीजों पर फोकस रखा। उन्होंने सबसे पहले प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बढ़ाया और दूसरा उन्होंने वैक्सीन की आपूर्ति को काम करने के लिए काम किया। वैक्सीन की आपूर्ति को पूरा करने के लिए अदार पूनावाला ने वैक्सीन बनाने वाली डच कंपनी को टेकओवर किया। इस अधिग्रहण के बाद अब अदार की कंपनी ज्यादा वैक्सीन बनाने वाली कंपनी बन गई।

बिल गेट्स से हुए प्रभावित
साल 2015 में बिल गेट्स ने अपने TED टॉक में कहा कि हमें बुद्ध से ज्यादा महामारी के बारे में सोचने और चिंता करने

की जरूरत है। बिल गेट्स की इस बात से अदार पूनावाला काफी प्रभावित हुए थे। वह उस समय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ थे। बता दें कि साल 2011 में अदार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ बने थे। अदार ने एक साक्षात्कार में कहा था कि बिल गेट्स की बातों ने उन्हें काफी प्रभावित किया। उन्होंने इसके बाद दवा निर्माण की क्षमताओं को आगे बढ़ाने की योजना बनाई। उनकी यही सोच वैक्सीन बनाने में भी काम आई।

अदार पूनावाला से जुड़े रोचक बातें

अदार पूनावाला कई बार चर्चा में आते हैं। अदार का ऑफिस भी काफी चर्चा में है। जी हाँ अदार ने एयरबस ए-320 को अपना फ्लाइटिंग ऑफिस बनाया है। वहीं उन्हें अपने पिता की तरह महंगी कारों का शौक है। उनके कार कलेक्शन में 20 से ज्यादा महंगी कारें हैं, जिसमें रॉल्स रॉयस, फेरारी, बेंटले और लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां शामिल हैं।

अदार ने यहां तक अपने बेटे के लिए एस350 मर्सडीज को बैटमैन की कार में बदलवा दिया। बता दें कि इस कार की एक्स-शोरूम कीमत 1.77 करोड़ रुपये से ज्यादा है। वहीं, साल 2020 में अदार ने 420 करोड़ रुपये का दान किया। यह दान उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को पूनावाला वैक्सीन रिसर्च बिल्डिंग बनाने के लिए किया।

अदार पूनावाला को किया गया सम्मानित

● दुनिया की मानी जाने वाली फॉर्च्यून मैगजीन में भी अदार पूनावाला का नाम शामिल हुआ था। अदार का नाम हेल्थ केयर कैटेगरी में 40 अंडर 40 की सूची में था।

● साल 2021 में टाइम्स मैगजीन में अदार पूनावाला का नाम दुनिया के प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया।

● अदार ने स्वच्छता पर कई काम किए। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अदार पूनावाला को स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एंबेस्डर भी बनाया है।

पेट्रोल-डीजल प्राइस हो गए जारी, टंकी फुल करवाने से पहले चेक करें लेटेस्ट रेट

देश की मुख्य ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 26 अक्टूबर 2024 (शनिवार) के लिए पेट्रोल-डीजल के दाम जारी कर दिये हैं। अगर आप भी तेल भरवाने पेट्रोल पंप जाने वाले हैं तो आपको एक बार लेटेस्ट रेट चेक करना चाहिए। दरअसल देश के सभी शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम अलग हैं। आइए जानते हैं कि आज आपके शहर में पेट्रोल-डीजल प्रति लीटर कितने रुपये में बिक रहा है।

नई दिल्ली। वर्ष 2017 से रोजाना सुबह पेट्रोल-डीजल के दाम अपडेट होते हैं। देश की मुख्य तेल कंपनियों इनके दाम को अपडेट करती हैं। देश के महानगरों समेत बाकी शहरों में भी पेट्रोल-डीजल के दाम अलग हैं। ऐसे में गाड़ीचालक को सलाह दी जाती है कि वह लेटेस्ट रेट चेक करने के बाद ही टंकी फुल करवाए।

बता दें कि इस साल मार्च 2024 में आम चुनाव से पहले पेट्रोल-डीजल के दाम में कटौती हुई थी। इसके बाद सभी शहरों में इनके दाम स्थिर बने हुए हैं। आज भी सभी शहरों में तेल के दाम जस

के तस बने हुए हैं। आइए, जानते हैं कि आज आपके शहर में एक लीटर पेट्रोल-डीजल कितने रुपये लीटर में मिल रहा है।

आज के लेटेस्ट रेट
इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, अलग-अलग शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol- Diesel Price 26 October 2024)

मेट्रोसिटी में पेट्रोल-डीजल के दाम

● दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और डीजल की कीमत 87.62 रुपये प्रति लीटर है।

● मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.44 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89.97 रुपये प्रति लीटर है।

● कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104.95 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.76 रुपये प्रति लीटर है।

● चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92.34 रुपये प्रति लीटर है।

बाकी शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम

● नोएडा: पेट्रोल 94.83 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.96 रुपये प्रति

लीटर
● गुरुग्राम: पेट्रोल 95.19 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.05 रुपये प्रति लीटर

● बंगलुरु: पेट्रोल 102.86 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.94 रुपये प्रति लीटर

● चंडीगढ़: पेट्रोल 94.24 रुपये प्रति लीटर और डीजल 82.40 रुपये प्रति लीटर

● हैदराबाद: पेट्रोल 107.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.65 रुपये प्रति लीटर

● जयपुर: पेट्रोल 104.88 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.36 रुपये प्रति लीटर

● पटना: पेट्रोल 105.18 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.04 रुपये प्रति लीटर

कैसे चेक करें लेटेस्ट रेट

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के वेबसाइट और ऐस पर से ताजा कीमत चेक किया जा सकता है। इसके अलावा पेट्रोल पंप का डीलर कोड लिखकर 92249 92249 पर मैसेज करके भी लेटेस्ट रेट जान सकते हैं। पेट्रोल पंप का डीलर कोड पता करने के लिए इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जाएं।

क्रिंटोकॉरेंसी के जोखिम पर भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने डाला प्रकाश, कहा- दुनिया के इकोसिस्टम के लिए बड़ा खतरा

क्रिंटोकॉरेंसी अवैध मुद्रा है। इसके बावजूद इसका इस्तेमाल कई लेनदेन के लिए किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों से इसमें हो रहे लेनदेन की संख्या में तेजी आई है। ऐसे में RBI Governor Shaktikanta Das का कहना है कि इसे वैश्विक स्तर पर पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। शक्तिकांत दास ने हाल ही बताया कि क्रिंटोकॉरेंसी कैसे वित्तीय तौर पर रिस्क पैदा कर रही है।

नई दिल्ली। क्रिंटोकॉरेंसी को लेकर ग्लोबली काफी क्रेज देखा जा रहा है। कई लोग स्टॉक की जगह पर इसमें निवेश करना पसंद करते हैं। हालांकि, यह कोई वैध मुद्रा नहीं है। इसके बावजूद लोग इसमें निवेश करते हैं। भारत में भी यह करेंसी वैध नहीं है।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास Peterson Institute for International Economics में आयोजित think-tank कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उन्होंने क्रिंटोकॉरेंसी कैसे चुनौती बन रहा है इसके बारे में कहा।

मनी स्प्लॉइड पर खोजा जाएगा कंट्रोल

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि क्रिंटोकॉरेंसी को बैन कर देना चाहिए। यह देश की आर्थिक

स्थिति पर बुरा प्रभाव डालता है। हाल ही में शक्तिकांत दास ने कहा कि क्रिंटोकॉरेंसी का असर मनी स्प्लॉइड पर पड़ेगा। अगर लोगों का झुकाव क्रिंटो की तरफ ज्यादा होता तो केंद्र बैंक अपना कंट्रोल मनी स्प्लॉइड पर खो सकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि क्रिंटो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ मौद्रिक स्थिरता के लिए भी खतरा है। शक्तिकांत दास ने कहा कि मैं इस पक्ष में हूँ कि जब कोई चीज फाइनेंशियल सिस्टम में मंजूर नहीं है तो इसे बैन करना ही अच्छा है।

अगर इसे समय रहते बंद नहीं करते हैं तो यह फाइनेंशियल तौर पर काफी रिस्क हन सकती है। अगर केंद्र बैंक का मनी स्प्लॉइड पर कंट्रोल खो जाता है तो इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ऐसे होने के बाद केंद्र बैंक फाइनेंशियल सिस्टम की लिक्विडिटी को चेक नहीं कर सकता है। इसके अलावा देश में महंगाई भी अपने चरम पर पहुंच जाएगी।

एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम क्रिंटो को एक बड़े जोखिम के रूप में देखते हैं। आज के समय में क्रिंटो की लेनदेन क्रॉस-कंट्री हो रहे हैं।

ग्लोबली तौर पर हो जाना चाहिए फैसेला

क्रिंटो के रिस्क को उजागर करते हुए दास ने कहा कि इस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैसला लेने

की जरूरत है। दरअसल, क्रिंटो से लेनदेन वैश्विक स्तर पर हो रहा है। यह केवल एक देश के लिए बल्कि सभी के लिए काफी जोखिम भरा है। ऐसे में सभी देशों के एकजुट होकर क्रिंटो के खिलाफ फैसला लेना चाहिए।

दास आगे कहते हैं कि क्रिंटो का चलन अगर इसी तरह आगे भी बढ़ता रहा तो इसका असर दुनिया के सभी केंद्र बैंकों पर पड़ेगा। सरकार धीरे-धीरे क्रिंटो से हो रहे जोखिम को लेकर सतर्क हो रही है।

क्रिंटो पर भारत ने उठाया पहला सवाल

इस साल भारत में जी-20 समिट में आयोजित हुआ था। इस समिट में भारत पहला देश था जिसने क्रिंटो करेंसी और जोखिम को लेकर सवाल उठाया था। जी-20 समिट में यह फैसला लिया गया कि अंतरराष्ट्रीय समझ के साथ क्रिंटोकॉरेंसी के इकोसिस्टम को समझा जाएगा।

शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई पहला केंद्र बैंक है जिसने क्रिंटो के जोखिम तो उजागर किया है। यह सभी देश के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए रिस्क है। यह एक सटीक कारण है कि इसे पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए।

ऐसे में हम यह कह रहे हैं कि हम क्रिंटो से काफी सावधानीपूर्वक निपटना चाहिए। हालांकि, यह केवल भारत का फैसला है। बाकी सभी देशों को अपने स्तर पर फैसला लेना चाहिए।

वित्तीय संकट से बचने के लिए आज ही इन आदतों को बोलें गुड़बाइ, फिर दिखने लगेगा कमाल

हम सभी वित्तीय तौर पर स्थिर रहने की कोशिश करते हैं पर हमारी कुछ गलत आदतों के कारण यह संभव नहीं हो पाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको वित्तीय तौर पर कोई परेशानी न हो तो इसके लिए आपको सेविंग करना शुरू करना चाहिए। हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि आपको इन आदतों को बोलें गुड़बाइ, फिर दिखने लगेगा कमाल

नई दिल्ली। जब भी कोई त्योहार या आपात स्थिति आती है तो हमारा ध्यान हमारे सेविंग पर जाती है। हम कैसे तो हमेशा पूरी कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सेविंग करे पर हमारी कुछ गलत आदतों की वजह से यह संभव नहीं हो पाता है। आज हम आपको कुछ फाइनेंशियल टिप्स के बारे में बताएंगे जिसके जरिये आप भी ज्यादा से ज्यादा सेविंग कर पाएंगे। यह सेविंग आपको फाइनेंशियल समस्याओं से बचाने में भी मदद करेगी।

अगर आपने इस दीवाली इन गलत आदतों को छोड़ दिया तो अगले साल की दीवाली तक आप देखेंगे कि आपके पास अच्छी-खासी राशि बची होगी, साथ ही आप वित्तीय तौर पर स्थिर होंगे।

सेविंग न करने की आदत
हम भले ही चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाएं पर हमारे बेजवाहरी खर्च करने की आदत महीने के अंत तक हमारे पास पैसे नहीं बचते हैं। ऐसे में हमें इस दीवाली अपने सेविंग न करने की आदत को छोड़ना होगा। आप सेविंग के लिए 50-30-20 रूल को फॉलो कर सकते हैं। इस रूल के अनुसार आपको हमेशा अपनी सैलरी का 20 फीसदी हिस्सा बचाना चाहिए।



इन्वेस्ट न करना
सेविंग के साथ इन्वेस्ट करना भी जरूरी है। आज के समय में इन्वेस्ट करने के लिए कई ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आपने अभी तक निवेश करना शुरू नहीं किया है तो इस दीवाली से आप यह करना शुरू कर सकते हैं। आप रिस्क के साथ निवेश के लिए एसआईपी, स्टॉक, बॉन्ड आदि में निवेश कर सकते हैं। वहीं, अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप एफडी, गोल्ड और सरकार द्वारा चलाई जा रही सेविंग स्कीम (Saving Scheme) में निवेश कर सकते हैं।

शौक के लिए कर्ज लेना
आज के समय में अच्छी लाइफस्टाइल को मैटेन करने के लिए लोग कर्ज लेते हैं। इसके

अलावा कहीं घूमने या फिर गाड़ी के शौक को पूरा करने के लिए कर्ज लेते हैं। इस तरह के कर्ज से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि यह एक तरह का दलदल है जो शुरुआत में तो सही लगता है पर बाद में यह काफी परेशानी खड़ी कर सकता है। इस दीवाली आपको संकल्प लेना चाहिए कि आप कभी भी अपने शौक के लिए कर्ज नहीं लेंगे।

हेल्थ इश्यूयर्स नहीं लेना
हम सभी चीजों पर ध्यान देते हैं पर अपनी सेहत पर ध्यान देना भूल जाते हैं। बीमारी कभी भी दस्तक देकर नहीं आती है। ऐसे में बीमारी से बचने के लिए आपको आज ही एक अच्छा हेल्थ इश्योरेंस (Health Insurance) प्लान खरीदना चाहिए। यह जरूरत के समय

आपको फाइनेंशियल तौर पर मदद भी करेगा और साथ ही आपके साथ आपके परिवार को सिक्योर भी करेगा। बता दें कि आप जितनी कम उम्र में इश्योरेंस प्लान खरीदते हैं उतना आपको भविष्य में लाभ मिलता है।

शौ ऑफ करना
अपने लाइफस्टाइल को मैटेन करने और शौ ऑफ करना अलग बात है। कई लोग शौ ऑफ के चक्कर में फिजूल खर्चा करते हैं। लोग महंगे होटल, पार्टी आदि में एक्सपेंस खर्च करते हैं, जो कि बेमतलब है। इन तरह के खर्चों से बचना चाहिए और कोशिश करें कि आप शौ ऑफ की आदत छोड़ दें। आप जितनी जल्दी ये आदत छोड़ेंगे उतना अच्छा रहेगा, वरना एक समय के बाद आपको पछताना पड़ेगा।

दीवाली से पहले सरकार का तोहफा, बिजनेस के लिए अब 10 लाख रुपये से ज्यादा का मिलेगा लोन

PM Mudra Yojana सरकार ने दीवाली से पहले प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है।

नोटिफिकेशन के अनुसार अब योजना के तहत लोन की लिमिट 10 लाख रुपये से बढ़कर 20 लाख रुपये हो गई है। अगर आप भी इस योजना का लाभ पाकर बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो आइए इस आर्टिकल में आवेदन का पूरा प्रोसेस जानते हैं।

नई दिल्ली। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) शुरू की थी। इस योजना में सरकार की तरफ से बिजनेस शुरू करने के लिए लोन (Loan) दिया जाता है। अब दीवाली से पहले सरकार ने योजना में बड़ा अपडेट किया है।

बढ़ा दिया लिमिट

सरकार ने इस योजना में मिल रहे लोन लिमिट को बढ़ा दिया है। जहां पहले बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार 10 लाख रुपये तक का लोन देती थी। अब इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने अपने बयान में कहा कि मुद्रा योजना (PM

Mudra Yojana) को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। सरकार ने मुद्रा योजना के लिमिट में इजाफा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

बजट 2024 (Budget 2024) पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की मौजूदा सीमा 10 लाख रुपये को बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाएगा। हालांकि, इसका लाभ उन लाभार्थी को मिलेगा जिन्होंने 'तरुण' श्रेणी के तहत लिए गए कर्ज को चुका दिया है।

कौन है योजना के पात्र

● केवल भारतीय नागरिक ही इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
● अगर आवेदक की बैंक डिफॉल्ट हिस्ट्री होती है तो वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
● किसी भी कॉर्पोरेट संस्था के लिए मुद्रा लोन नहीं लिया जा सकता है।
● आवेदक के पास बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है।
● आवेदक की आयु कम से कम 18 साल की होनी चाहिए।

कई कैटेगरी में मिलता है लोन

इस योजना के तहत लोन के लिए सरकारी और प्राइवेट बैंक के साथ त्रयी ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉन फाइनेंशियल कंपनियों में भी अप्लाई किया जा सकता है। मुद्रा योजना में लाभार्थी को तीन कैटेगरी में लोन मिलता है। इस योजना में लोन की लिमिट भी

तीन तरह की होती है। आवेदक को शिशु, किशोर और तरुण के तहत लोन दिया जाता है।

कैसे करें अप्लाई

● पीएम मुद्रा योजना की अधिकारिक वेबसाइट (mudra.org.in) पर जाएं।
● अब अपने हिसाब से लोन की तीन कैटेगरी में से कोई एक सेलेक्ट करें।
● इसके बाद न्यू पेज ओपन होगा, जहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
● एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करें।
● अब अपने नजदीक के बैंक जिसमें आपका अकाउंट है। उसमें जाकर फॉर्म सबमिट कर दें।
● फॉर्म सबमिट करने के बाद बैंक इसे वेरिफाई करेगी और एक महीने के भीतर आपको लोन मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको इसके लिए यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई करना होगा।

ये डॉक्यूमेंट्स है जरूरी

लोन के लिए आवेदन देते समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लानानी होगी। आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, परमानेंट एड्रेस प्रूफ, बिजनेस के स्थान का एड्रेस प्रूफ, इनकम टैक्स रिटर्न और सैलरी टैक्स रिटर्न के साथ पासपोर्ट साइज फोटो की कॉपी अटैच करनी होगी।



भारत में 12 वर्षों बाद 18 वॉ एशिया प्रशांत जर्मन कॉन्फ्रेंस 25 अक्टूबर 2024 का आगाज - जर्मन की फोकस ऑन इंडिया रणनीति का अभिनंदन

भारत आज लोकतंत्र, जनसांख्यिकी, मांग और डाटा के मजबूत स्तंभों पर खड़ा है भारत की कुशल मैनोपावर पर भरोसा जताकर वीजा की सीमा 20 से 90 हजार करना व फोकस ऑन इंडिया, जर्मन रणनीति को रेखांकित करना होगा- एडवोकेट किशन मनसुखदास भावनाजी गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया- वैश्विक स्तर पर दुनियाँ देख रही है कि भारत के पड़ोसी देश अपनी-अपनी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं जैसे बांग्लादेश में फिर नईसा भड़क उठी है, पीएम के स्टीफे पर का प्रूफ नहीं मिलने से संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है, पाकिस्तान के खैबर पश्तून में बम धमाकों व आंतरिक कलह, तो श्रीलंका का संकट दुनिया देख चुकी है नेपाल में सत्ता परिवर्तन 30-50 पर हुआ है, परंतु भारतीय सरकार हैट्रिक 5.0 के आगाज पर वापसी कर रिकॉर्ड बनाया है, व तेजी से विजन 2047 पर चल पड़ी है तथा इस यात्रा में सफलता के नए-नए अध्याय जोड़ते जा रहे हैं जिससे दुनिया दंग है, व भारतीय बौद्धिक क्षमता पर सटीक विश्लेषण हो चली है, क्योंकि दुनियाँ जानती है भारत आज मजबूत लोकतंत्र जनसंस्कृतियंत्र, मांग और डाटा रूपी चार स्तंभों पर मजबूती से खड़ी है। आज हम यह चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जर्मन चांसलर अपने लाव लश्कर के साथ 24 से 25 अक्टूबर 2024 तक भारतीय दौरे पर हैं तथा उन्होंने भारत की भर भर कर तारीफ की, क्योंकि भारत रूस-यूक्रेन युद्धशान्ति के भरपूर प्रयास कर रहा है तथा उन्होंने भारतीय टैलेंट श्रमिकों टेक्नीशियन की बौद्धिक क्षमता को पहचाना है व वीजा अब 20 से बढ़कर 90 हजार लोगों के लिए खोला दी है इससे उनके प्रभावित होने का अंदाजा लगाया जा सकता है, वहीं सम्मेलन में करीब 27 सम्मेलीता पर हस्ताक्षर हुए हैं जो बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के

सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, भारत में 12 वर्षों बाद 18 वॉ एशिया प्रशांत जर्मन कॉन्फ्रेंस 25 अक्टूबर 2024 का आगाज जर्मन की रणनीति फोकस ऑन इंडिया का अभिनंदन करते हैं।

साथियों बात अगर हम 18 वॉ एशियाई प्रशांत कॉन्फ्रेंस 25 अक्टूबर 2024 की करें तो, यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भारतीय पीएम और जर्मनी के चांसलर ने शिरानकत की। पीएम ने भारतीय आकांक्षाओं, विकसित भारत का रोडमैप और तकनीक और स्किल को बढ़ाकर दुनियाँ को भरोसा दिलाया कि भविष्य को संभालने का समाधान देने में भारत सक्षम है। 112 साल बाद भारत एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस की मेजबानी कर रहा है, पीएम ने कहा कि एक ओर सीईओ फोरम की मीटिंग चल रही है और दूसरी ओर दोनों देशों को नौसेना युद्धभ्यास कर रही हैं, यह दर्शाता है कि हर स्तर पर भारत और जर्मनी के संबंध मजबूत हो रहे हैं देखें पीएम ने शुरुआत को जर्मन कंपनियों को देश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि निवेश के लिए भारत से बेहतर कोई स्थान नहीं है और देश की विकास गाथा में शामिल होने का यह सही समय है पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि विदेशी निवेशकों के लिए भारत की मेक इन इंडिया प्रोग्राम में शामिल होने और मेक फॉर द वर्ल्ड में शामिल होने का यह सही समय है। उन्होंने यह भी कहा कि जर्मनी ने भारत की कुशल जनशक्ति में जो विश्वास व्यक्त किया है, वह अद्भुत है क्योंकि यूरोपीय राष्ट्र ने कुशल भारतीय कार्यबल के लिए वीजा को 20 से बढ़ाकर 90 हजार करने का निर्णय लिया है, यह जर्मनी के विकास को नई गति देगा। उन्होंने कहा कि हमने आने वाले 25 वर्षों में विकसित भारत का रोडमैप तैयार किया है। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण समय में जर्मन कैबिनेट ने भारत पर ध्यान दस्तावेज जारी किया है। उन्होंने कहा, भारत



की विकास गाथा में शामिल होने का यह सही समय है। भारत वैश्विक व्यापार और विनिर्माण केंद्र बन रहा है, उन्होंने कहा कि आज भारत लोकतंत्र, जनसांख्यिकी, मांग और डाटा के मजबूत स्तंभों पर खड़ा है, भारत सड़कों और बंदरगाहों में रिकॉर्ड निवेश कर रहा है और इंडो-पैसिफिक रीजन दुनियाँ के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे कहा, भारत और जर्मनी के बीच सातवें इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन का भी आयोजन हुआ है। इसके अलावा व्यापार और सामरिक साझेदारी के मोर्चे पर भी दोनों देशों के बीच चर्चा महत्वपूर्ण रही। पीएम ने जर्मनी की फोकस ऑन इंडिया रणनीति के लिए अभिनंदन किया और कहा कि इसमें विश्व के दो बड़े लोकतंत्रों के बीच साझेदारी को व्यापक तरीके से आधुनिक बनाने और ऊंचा उठाने का ब्लूप्रिंट है।

साथियों बात अगर हम जर्मनी चांसलर द्वारा कार्यक्रम में संबोधन करने की करें तो, उन्होंने कहा, यह स्पष्ट है कि हमें अधिक सहयोग की आवश्यकता है। वैश्वीकरण सभी देशों की सफलता की कहानी रही है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के कई देश इसके उदाहरण हैं। उन्होंने आगे कहा, 21 वीं सदी की दुनियाँ कुछ ऐसी है, जहां हमें प्राणिक के लिए काम करना है। वह भूवीय दुनियाँ में

कोई वैश्विक पुलिसकर्मी नहीं, कोई नियम, संस्थान नहीं। हममें से प्रत्येक को इसकी रक्षा करने के लिए बुलाया गया है। अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में सफल होता है तो इसका परिणाम यूरोपीय सीमाओं से परे होगा। इससे वैश्विक सुरक्षा खतरे में पड़ सकता है। मध्य-पूर्व में भी तनाव जारी है। कोरियाई प्रायद्वीप दक्षिण-पूर्वी चीन सागर सभी युद्धबिंदु पर हैं। आगे कहा, आज हमारे विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों का सबसे बड़ा समूह भारतीयों का है। पिछले वर्ष ही जर्मनी में काम करने वाले भारतीयों की संख्या में 23 हजार की वृद्धि हुई। यह प्रतिभा हमारे श्रम बाजार में स्वागत योग्य है। उन्होंने बताया कि जर्मनी अपनी वीजा प्रक्रिया का डिजिटलीकरण से पहले जर्मन व्यवसायों की एक बैठक को संबोधित करते हुए चांसलर ने भारत के बारे में कई सकारात्मक बातें कहीं, भारत की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि यह दुनियाँ का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और दुनियाँ के सबसे गतिशील प्रांत एशिया प्रशांत का केंद्र है। हालांकि चांसलर ने व्यापार फोरम में बोलते हुए अनियमित आप्रवासन के बारे में चेतावनी और कहा कि जर्मनी कुशल कामगारों का स्वागत करता है, लेकिन किसे आने देना है और किसे नहीं इसका फैसला वह ही करेगा। तकनीक, कौशल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा से लेकर खुफिया जानकारी साझा करना और कानूनी मामलों में सहायता जैसे क्षेत्रों में सहयोग कार्यक्रमों की घोषणा की गई। मुक्त व्यापार के मोर्चे पर शान्ति से कुछ छिपे हुए संदेश भी देने की कोशिश की, उन्होंने संरक्षणवाद का स्पष्ट रूप से विरोध किया और कहा कि विश्व व्यापार संगठन की बनाई व्यवस्था को मानना चाहिए और तब-तब के शुल्क लगाने से बचना चाहिए। भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच

मुक्त व्यापार संधि (एफटीए) कराने की जर्मनी की कोशिशों का भी जिक्र किया और कहा कि अगर दोनों देश इस पर मिलकर काम करें, तो यह सालों की जगह कुछ ही महीनों में हो जाएगा। एफटीए पर अलग से भी दोनों देशों के बयान आए, जिनसे संकेत मिलता है कि अभी इस पर बहुत काम होना बाकी है। जर्मनी के चांसलर और आर्थिक मामलों के मंत्री ने कहा कि एफटीए पर चर्चाओं में कृषि क्षेत्र एक मुश्किल विषय बना हुआ है। भारत के व्यापार मंत्री ने भी कहा कि ईयू के लिए अपना डेयरी बाजार नहीं खोलेगा और अगर इस पर जोर दिया गया, तो एफटीए होना मुश्किल है। 2022 में दोनों ही पक्षों ने 2023 तक एफटीए को संपन्न करने की बात की थी, लेकिन यह अभी तक हो नहीं पाया है।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि भारत में 12 वर्षों बाद 18 वॉ एशिया प्रशांत जर्मन कॉन्फ्रेंस 25 अक्टूबर 2024 का आगाज-जर्मन की फोकस ऑन इंडिया रणनीति का अभिनंदन। भारत आज लोकतंत्र जनसांख्यिकी मांग और डाटा के मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। भारत की कुशल मैनोपावर पर भरोसा जताकर वीजा की सीमा 20 से 90 हजार करना व फोकस ऑन इंडिया जर्मन रणनीति को रेखांकित करना होगा।

**संकलनकर्ता
लेखक-कवि
विशेषज्ञ
स्तंभकार
साहित्यकार
अंतरराष्ट्रीय
लेखक/चिंतक**



सि.ए.टी.सी. एडवोकेट किशन मनसुखदास भावनाजी गोंदिया महाराष्ट्र

'समाज के लिए करुणा की भावना ने मुझे जज बनाए रखा', सीजेआई चंद्रचूड़ ने दलित छात्र के पक्ष में दिए फैसले की कहानी सुनाई

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि समाज के प्रति उनकी करुणा की भावना ने ही एक न्यायाधीश के रूप में उन्हें निरंतरता प्रदान की है। खासकर मामलों की पड़ताल जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर। पड़ताल का तत्व हमारे काम में शामिल है। इससे कोई भी चीज छूटती नहीं है। पड़ताल का यह तत्व हमारे न्यायालय के काम को निर्देशित करता है।



नई दिल्ली। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि समाज के प्रति उनकी करुणा की भावना ने ही एक न्यायाधीश के रूप में उन्हें निरंतरता प्रदान की है, खासकर मामलों की पड़ताल जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर। पड़ताल का तत्व हमारे काम में शामिल है। इससे कोई भी चीज छूटती नहीं है। पड़ताल का यह तत्व हमारे न्यायालय के काम को निर्देशित करता है। लेकिन न्यायाधीश के रूप में हमें बनाए रखने वाली चीज उस समाज के प्रति हमारी करुणा की भावना है, जिसके लिए हम न्याय करते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उन्हें बांबे हाई कोर्ट में वकीलों के संघ द्वारा सम्मानित किया गया। सीजेआई ने एक ऐसे मामले का उल्लेख किया, जिसमें उस दलित छात्र को राहत दी गई थी, जो समय पर आइआइटी धनबाद में प्रवेश शुल्क का भुगतान नहीं कर सका था। उन्होंने कहा, लड़का वंचित पृष्ठभूमि से आता था। वह 17,500 रुपये की प्रवेश फीस भी नहीं दे सका था। अगर हमने उसे राहत नहीं दी होती, तो उसे कालेज में प्रवेश नहीं मिलता। यही वह चीज है, जिसने मुझे इतने सालों तक न्यायाधीश के रूप में बनाए रखा। राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, जयपुर ने मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को शिकायतें प्रस्तुत की हैं। बार ने उच्च न्यायालय प्रशासन की ओर से शुक्रवार को आयोजित हुए दिवाली स्नेह मिलन का भी बहिष्कार किया और बार ने वकीलों के लिए अलग से स्नेह मिलन आयोजित किया।

दिवाली का त्यौहार

आया दिवाली का त्यौहार, इसमें खुशियां मिले हजार। जगमगा-जगमगा दीप जले, उजियारों से हर घर खिले। एक-दूजे के हम गले मिले, बड़ों का आशीर्वाद हमें मिले।

आया दिवाली का त्यौहार, इसमें खुशियां मिले हजार। हर घर हो गई रंगाई-पुनाई, खिले आंगन धूप भी मुस्कंदाई। मम्मी भी लाई खील-बताशे, पापाजी लाए लक्ष्मी की मूर्ति! आई है पूजा सामग्री हुई पूर्ति।

आया दिवाली का त्यौहार, इसमें खुशियां मिले हजार। खूब हुई सभी दूर रोशनाई, रात भी जैसे दिन लेकर आई। आ जाओ खूब पटाखे फोड़ो, लो खाओ मिठाई मुंह खोलो! पूरे परिवार को बधाई दे दो।

संजय एम. तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
इंदौर (मध्य प्रदेश)
98260-25986

चक्रवात पर राज्य सरकार श्वेत पत्र जारी करे : बिजेड़ी



मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओडिशा

भुवनेश्वर: बिजेड़ी ने तूफान के साथ राज्य सरकार पर जमकर बरसे। चक्रवात के समय हवा की गति अनुमान से काफी कम थी, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। ऐसे तूफान में लोगों को निकालना अनावश्यक था। चक्रवात फनी के दौरान 185 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। उस वक्त 10 लाख लोगों को निकाला गया था। इसलिए सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इस तूफान में वास्तव में कितने लोग विस्थापित हुए। इसके लिए श्वेत पत्र जारी करें बिजेड़ी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐसा दावा किया बिजेड़ी नेत्री सामंतसिंघर ने कहा कि सरकार को जनता को यह जानकारी देनी चाहिए कि तूफान के कारण कितने लोग विस्थापित हुए हैं और कितने लोग आश्रय स्थलों में रह रहे हैं। बिजेड़ी का आरोप है कि राज्य में तूफान से 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 3 लोगों की जान राजनगर में गई और एक व्यक्ति की जान मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र में गई बिजेड़ी ने कहा कि राज्य सरकार को जीरो को जेनुअल्टी वाला श्वेत पत्र लाना चाहिए और झूठ को सच साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने भी तूफान में नवीन सरकार के मांडल की सराहना की। 1999 में, राज्य में केवल 23 चक्रवात आश्रय स्थल थे। 2024 में, संख्या 900 थी, जिनमें से 450 आल्पाधुनिक चक्रवात आश्रय थे। 24 साल में ओडिशा ने कई आपदाएं झेली हैं।

'बम अफवाह की पोस्ट हटाएं', विमानों को धमकी पर केंद्र सरकार सख्त; सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दिए अहम निर्देश

देश में पिछले कुछ दिनों से लगातार विमानों को बम की धमकी दी जा रही है। इसको लेकर केंद्र सरकार सख्त हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने कहा कि इस प्रकार की हरकत करने वालों की सूचना सरकार को देना उनकी जिम्मेदारी होगी। बता दें कि शुक्रवार को भी 25 से ज्यादा विमानों को धमकी मिली थी।

नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय ने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म के साथ सभी सोशल मीडिया से कहा है कि वह अपने प्लेटफॉर्म से बम की अफवाह जैसी खबरों को प्रेषित नहीं होने दें। अगर इनके प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसा करता है तो इस प्रकार की झूठी खबर को प्लेटफॉर्म से हटाना, इस प्रकार की हरकत करने वालों की सूचना सरकार को देना उनकी जिम्मेदारी होगी। अन्यथा उन्हें आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अज्ञान भुगतने के लिए तैयार रहना होगा।

लगातार मिल रही बम की अफवाह
गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हवाई जहाज में बम की अफवाह



फैलाई जा रही है। पिछले एक सप्ताह में 125 से अधिक बार जहाज में बम होने की झूठी खबर फैलाई गई है। इससे यात्रियों में घबराहट के साथ एयरलाइंस का करोड़ों का नुकसान हुआ है।

मंत्रालय का कहना है कि सोशल मीडिया और इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म पर खबरों को फॉरवर्ड करने, रि-पोस्ट करने या रि-ट्वीट करने का विकल्प होने से बम की अफवाह जैसी खबरें खतरनाक रूप ले रही हैं और इससे यात्रियों की सुरक्षा के साथ देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होने की आशंका पैदा हो रही है। इसलिए इंटरमीडिएट के साथ सभी

सोशल मीडिया का यह दायित्व है कि इस प्रकार के पोस्ट को अपने प्लेटफॉर्म पर चलने से रोके और उसे तुरंत हटाने के साथ 72 घंटे के भीतर सरकार को इस प्रकार के पोस्ट डालने वालों की जानकारी दे।

शुक्रवार को भी मिली अफवाह
शुक्रवार को 27 घंटे लंबी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को धमकी मिली, जो फर्जी निकलीं। गुरुवार को देशभर में 83 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। पिछले 12 दिनों में भारतीय विमानन कंपनियों द्वारा संचालित 300 से अधिक उड़ानों को बम की धमकी मिली है। ज्यादातर धमकियां इंटरनेट मीडिया के जरिये

दी गईं। इन धमकियों को देखते हुए देश के हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए गए हैं।
इंडिया के प्रवक्त को कहा कि कोडिफाइड से दम्पन (संरुद्धि अरब) जाने वाली 6ई 87 उड़ान समेत सात उड़ानों को सुरक्षा से संबंधित सूचना मिली। विस्तारा और स्प्राइजेट की सात-सात उड़ानों को भी धमकी मिली है, जबकि एअर इंडिया की छह उड़ानों को धमकियां मिलीं। दिल्ली से दरभंगा जाने वाली स्प्राइजेट की प्लाइट में बम होने की सूचना मिली। विमान के एयरपोर्ट पहुंचने पर सभी यात्रियों की तलाशी ली गई। जांच के दौरान बम होने की सूचना झूठी निकली।

अंतरराष्ट्रीय सामाजिक ट्रस्ट ने छात्राओं को पटाखे रहित दिवाली मनाने का संकल्प दिलाया: डॉ हृदयेश कुमार



राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सीही सेक्टर 8 के प्रांगण में दिवाली के उपलक्ष्य में दीपोत्सव मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एन टी पीसी से पंकज अरोड़ा, गौरी गौड़, शिवेन्द्र, शिवालिक कम्पनी से रोहतास, निधि एवं रोटरी क्लब से माधवी हंस, बी आर सी डाक्टर कमल चौधरी, पूर्व प्राचार्य डाक्टर रोहतास, पूर्व प्राचार्य विजेन्द्र ने मेले का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर रिबन काट कर किया। इस

अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जयप्रकाश वैष्णव ने पौधे भेंटकर व माला पहनाकर सभी अतिथियों का अभिनंदन कर स्वागत किया। कार्यक्रम में छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और प्रत्येक कक्षा की छात्राओं ने अपने-अपने स्टाल लगा कर अपने हाथों से बनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई। कार्यक्रम में छात्राओं ने अपने हाथों से बने खाने के व्यंजनों की भी स्टाल लगाई। इस अवसर पर प्रथम व द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी पाने वाली कक्षाओं की



छात्राओं को व वालंटियर छात्राओं को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों ने कहा की सरकारी स्कूलों में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। मंच संचालन से अखिल भारतीय मानव कल्याण ट्रस्ट के संस्थापक डॉ हृदयेश कुमार ने सभी छात्राओं व अध्यापकों को पटाखे रहित दिवाली मनाने का संकल्प दिलाया और कहा कि पटाखे चलाना बेफजूल खर्चा है। पर्यावरण प्रदूषित होता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विद्यालय के

प्राचार्य डॉक्टर जयप्रकाश वैष्णव ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त कर धन्यवाद किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विद्यालय के प्राचार्य व सभी अध्यापकों एवं छात्राओं को बी आर सी डाक्टर कमल चौधरी ने सराहना करते हुए दिवाली की बंधाईयां व शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम को सफल बनाने में नीतू देविना, निशा, नीलम, देवलता, आशु गांधी, रोहित, जावेद शेख ने अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम में एसएमसी केमटी की प्रधान, गणभाय्य लोग विशेष रूप से उपस्थित थे।

यूरिका 2024: सृजन और नवाचार का त्यौहार मुख्य अतिथि: त्रिपुरा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री. T. अमरनाथ गौड़.

परिवहन विशेष न्यूज
इंडस यूनिवर्सल स्कूल: सैनिकपुरी में स्थित इंडस यूनिवर्सल स्कूल, छात्रों की रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम एक प्रमुख शैक्षिक संस्थान है। स्कूल की टीम, वित्त और प्रशासन विभाग के प्रमुख श्री डी. किशन और प्रिंसिपल श्रीमती के. वी. नीलिमा के नेतृत्व में, इस त्यौहार का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम छात्रों की प्रतिभा को उजागर करने और अभिभावकों और शिक्षकों के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छात्रों ने अपने नवीनतम परियोजनाओं और विचारों के साथ इस उत्सव में भाग लिया और सभी को आकर्षित किया। मुख्य अतिथि-इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित त्रिपुरा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री टी. अमरनाथ गौड़ ने छात्रों की प्रतिभा की विशेष प्रशंसा की और इस विविधता से भरे त्यौहार के आयोजन के लिए स्कूल टीम को बधाई दी। उन्होंने स्कूल टीम की मेहनत और इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन में उनकी प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित किया, जो छात्रों के विकास में सहायक होती है।

श्री. श्रेयस-इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पहचान पाने वाले छात्र भी, श्रेयस ने ताइक्वांडो में अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उन्होंने तीन साल की उम्र में ताइक्वांडो सीखना शुरू किया और अपनी पहली बेल्ट प्रसिद्ध तेलुगु फिल्म अभिनेता सुमन लवार से प्राप्त की। वर्तमान में,



उन्के पास कुकिक्वोन ताइक्वांडो में पहला डान (First Dan) है और उन्होंने अद्भुत विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है।
इस कार्यक्रम में, वी. श्रेयस ने 30 सेकंड में 100 स्पीड किक्स करके अद्भुत विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने नंचक पूसे प्रदर्शन में भी अपने कौशल का प्रदर्शन किया, जो ताइक्वांडो में उनकी विशेषता को दर्शाता है। इस कौशल को देखकर न्यायाधीश ने उनकी सराहना की।